

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 6 मार्च 1979

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 28
अतारांकित प्रश्न उत्तर	(5) 29
ध्यानाकर्षण सूचनाएं—	
(i) उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि संबंधी	(5) 31
(ii) हरियाणा के डाकखानों में बेनामी जमा रकियों संबंधी	(5) 31
(iii) टपरीवासियों तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित	
जनजातियों की सूची में शामिल करने संबंधी	(5) 32
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(5) 33
सदन की मेज पर पुनः रखे गये कागज-पत्र	(5) 34

वर्ष 1978-79 के लिए अनुमान (तीसरी किस्त)

पे ा करना (5) 34

वर्ष 1978-79 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)

पर ऐस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्ट (5) 34

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा

धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (5) 35

औचित्य प्र ण (5) 39

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा

धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (5) 40-80

हरियाणा विधान सभा

मंगलवारर, 6 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर - 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Permanent Anti-floods measures in the state

***903. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) Whether there is any scheme under consideration of the Government

(b) If so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be finalised?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):

(क) जी, हां

(ख) 138.32 करोड़ रूपये की लागत का एक मास्टर प्लान बनाया है। कुछ एक योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ से अधिक प्रभावित क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में राहत देने के लिए इन योजनाओं का पहला चरण जिसकी लागत लगभग 50.00 करोड़ रूपये है, तीन साल तक पूर्ण करने प्रस्ताव है। सारे मास्टर प्लान का पूरा करना धन की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

स्वामी आदित्य दे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह मास्टर प्लान क्या है तथा उसके लिए अब तक कितना धन प्राप्त कर लिया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान के तहत काफी प्रोजेक्ट्स हैं। जो जरूरी और बड़े कार्य हैं, उनके नाम में बता देता हूँ, जो इस प्रकार हैं:—

Ujina Diversion Drain.

Chhudani Bahagurgarh Complex

Pundri Drain complex

Increasing capacity of Gouchi Drain.

Raising and strengthening left bank of outfall drain

No. 8

Deepening bed of diversion Drain No. 8

Remodeling bed of diversion Drain No. 8

Remodeling bed of diversion Drain No. 8

Jhajjar Ring Bund with outfall Drain.

Constructing link drain for Karnal, Rohtak and Sonapat Distt.

Construction Ring Bunds in Gurugram Distt.

Construction Masani Barrage of Sahibi Nadi

Kotla Storage Project.

Bhindawas Lake Storage Project

Bhindawas Lake Storage Project

Raising Pond Level of Ghaggar.

Village tanks to be deepened for flow marooned villages

Ring Bunds around villages likely to be marooned.

स्वामी आदित्य वे T: अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान के लिए कितना धन उपलब्ध हो चुका है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जितना धन एक साल के लिए निर्धारित किया जाता है वह सारा ही खर्च किया जाता है। इन तीन सालों के अन्दर 50 करोड़ रुपये खर्च करने की सम्भावना है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर न तो ड्रेन

खोदी गई है और न ही कोई लिक ड्रैन्ज खोदी गई ललेकिन वहां पर वाटर लोगिंग और सीपेज ने फ्लड का रूप ले लिया है। क्या उसको रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, नहर पक्की बनाने का प्रोग्राम चालू है और जिन एरियाज में सीपेज और वाटर लोगिंग की वजह से फ्लड आता है, यह प्रोब्लम नहरें पक्की हो जाने से दूर हो जाएगी।

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र जिले में मारकण्डा का पानी काफी नुकसान कर रहा है। मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या सरकार का इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रबन्ध करने का ख्याल है।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यमुना नदी का 2 साल से इतना प्रकोप हो रहा है। जिससे लोगों को काफी परेशानी है क्या इस नदी का नाम भी इस मास्टर प्लान में है या मास्टर प्लान से बाहर है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष, मास्टर प्लान के तहत जिन प्राजैक्ट्स का नाम मैंने अभी लिया है उनके मोटे-मोटे काम शुरू हो गए हैं यमुना का प्रकोप, कंवर साहब के एरिया और बाकी लोगों के एरियाज पर है, वहां पर भी काम किया जाएगा।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बार यमुना के अन्दर जो फ्लड

आया है उससे ज्यादा नुकसान हरियाणा को हुआ है और यू०पी० के अन्दर एम्बैकमेंट्स का काम अच्छा है इसलिए हरियाणा में ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या यू०पी० गवर्नमेंट के साथ हमारी सरकार ने इस बारे में कोई मीटिंग की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: एक कमेटी बनी हुई है। यू०पी० गवर्नमेंट को इससे कोई ताल्लुक नहीं है हम उस कमेटी से वक्तन फक्तन रिक्वेस्ट करते रहते हैं और हम यह चाहते हैं कि यह काम किया जाए जिससे हमारे इलाके को फायदा पहुंचे।

चौधरी पीर चन्द: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जाखल के साथ गांव 18 गांव है और वहां एक रंगोई लाना है उस नाले को खुदवाने के लिए पिछले सै न में भी वि वास दिलाया गया था लेकिन उसका नाम इन प्राजैक्ट्स में नहीं है। क्या उन गांवां को बचाने के लिए उस नालेको खुदवाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सै न में माननीय सदस्य को वि वा भी दिलाया था और बड़ी खुशी की बात है रंगोई नाले के लिए हमारे मुख्य मंत्री दजी ने स्वयं आदेश भी दे दिया है। उस पर कार्यवाही जरूरी होगी पर हर आईटम का नाम बताना मुश्किल है।

चौधरी राम किशन: स्पीकर साहब, पिछले सै न में मंत्री महोदय ने वि वास दिलाया था कि सफीदों के 65 गांवों में से 47 गांव जो बाढ़ की लपेट में आते हैं वहां उसकी रोकथाम की

जाएगी। यहां एक भम्भेवा गांव है जहां एक मंजूर उदा ड्रेन है। वह सारी इनकम्पलीट है। क्या मंत्री महोदय आ वासन देगें कि आगे आने वाले वर्ष से पहले-पहले इस ड्रेन को कम्पलीट करवा दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय एरिया की जो ड्रेन्ज है। उनका इस मास्टर प्लान में कुछ झगड़ा है। मैं इनको यह वि वास दिला दूं कि 30 जून, 1979 तक जो काम करने है वह पूरे हो जाएंगे।

डा० बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अम्बाला जिले को इस मास्टर प्लान से बाहर निकाला हुआ है? अम्बाला जिले में एक पिजोरा ड्रेन है, वह बहुत तबाही मचाती है। क्या इस मास्टर प्लान में वह नदी शामिल की जाएगी या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस मास्टर प्लान के अन्दर तमात हरियाणा के एक एरियाज शामिल किए गए है जहां पर फ्लडज आने की सम्भावना हैं यह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सब के नाम लेना असम्भव है।

चौधरी जिले सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में फ्लड की कोई बात नहीं है। हमारे यहां जो नहर निकाली जा रही है वह गलत निकाली जा रही है।

(इस प्र न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मास्टर विठ्ठल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि घग्गर नदी में बाढ़ न आने की वजह से इस बार तो अम्बाला जिले के गांव बाढ़ग्रस्त नहीं हुए लेकिन भविष्य में बचाव के लिए पंजाब ने तो अपनी ओर बांध बांध लिया है तो क्या हरियाणा सरकार को भी उस नदी पर कोई बांध बांधन की योजना है? यदि है तो उसे कब तक अमलीजामा पहनाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा की बात इसी सवाल में पूछने लग गए तो फिर मैं यही कहूंगा कि इसलिए एक सैपरेट नोटिस दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यह बड़ा जरनल सवाल है और इस वक्त हर एक चीज के बारे में पर्टीकुलर जवाब मंत्री जी के पास नहीं है। आप सप्लीमैटरी थोड़ा जनरल न रखे और ड्रेन्ज के बारे में ही सवाल करें।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि पहले चरण का काम भुरू हो गया है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी जगह काम भुरू कर दिया गया है या कि कुछ इलाकों में किया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जहां फ्लडज ज्यादा आता रहा है, वहां पर प्रायर्टी से काम भुरू किया गया है।

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, जिला सोनीपत में काम बड़ा सुस्ती के साथ हो रहा है और अप्रैल महीने से कटाई

का काम भी भुरू हो जाएगा और उस वक्त मजदूरों की समस्या भी हो जाएगी। क्या सरकार ऐसे आदे 1 जारी करेगी कि जिला सोनीपत में भी एक ड्रेन खोदी जाए?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अब काम चुस्ती से करवाया जाएगा।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, सिरसा में घग्गर नाले पर जो बांध बांधा जा रहा था, वह कम्प्लीट नहीं हुआ है। उसका काफी काम बाकी है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बाकी काम को पूरा करके इस बांध को कब तक कम्प्लीट करवाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: कामरेड भांकर लाल ने कल 10-12 जगहों का नाम दिया था, वह मैंने नोट कर लिया है, अगर आव यक होगा तो जरूर बांध बांधा जाएगा।

चौधरी लाल सिंह: मैं अपने पापुलर मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि नारायणगढ़ के एरिये से सारी नदियां निकलती है। क्या उस एरिये को नदियों द्वारा की गई तबाही से बचाया जाएगा?

(इस प्र न को कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Construction of Sutlej Yamuna Link Canal

***881. Sh. Shamsheer Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) The expenditure incurred by the Haryana Government on the construction of S.Y.L. so far;

(b) The amount of loss being suffered by the state by way of interest on expenditure incurred on construction and on account of machines, tools establishment etc. lying idle due to non-completion of above referred to canal;

(c) The time by which the S.Y.L. canal is likely to be completed;

(d) Whether the S.Y.L. canal is likely to be completed within the scheduled period; if not, how much time beyond the scheduled period is likely to be taken;

(e) Whether the Government has assessed the loss in terms of water and crops; if so, the details thereof; ; and

(f) The steps taken or proposed to be taken to get the work of S.Y.L. canal executed in the Punjab territory?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) सतलुज यमुना लिंक परियोजना पर नवम्बर, 1978 तक का खर्च रुपये 23.96 करोड़ हुआ है।

(ख) कैपिटल एक्सपैन्डीचर पर लगभग 1.50 करोड़ रुपये सालाना का ब्याज जो आयेगा इसमें सरकार को मीन टूल्ज तथा एसटैबलि मेंट पर कोई हानि नहीं हुई क्योंकि यह मीन वगैरा परियोजना की पूर्ति पर दूसरे कार्यों के लिये तबदील की जाएगी।

(ग) इस नहर का हरियाणा में स्थित भाग 30-6-79 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) हां

(ङ) पानी और फसलों की हानि का अनुमान इस नहर क हरियाणा के हिस्से की निश्चित तारीख पर पूर्ण होने पर ही लगाया जा सकेगा। पंजाब सरकार की सहमति न होने के कारण यह मामला प्रधान मंत्री महोदय, के सम्मुख तीव्रता के साथ रखा गया। इस विषय में चार बैठके 26-8-78, 2-9-78, 8-9-78 तथा 20-9-78 को हुई आखरी तारीख पर प्रधान मंत्री महोदय, ने अपने विचार स्पष्टता से व्यक्त किये परन्तु पंजाब सरकार ने इसका पालन अभी तक नहीं किया। इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार ने प्रधान मंत्री महोदय को अवगत करा दिया है।

श्री भामेरा सिंह: मैं मंत्री महोदय का ध्यान इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर में छपी एक न्यूज आइटम की तरह दिलाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि कल पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने पंजाब असेम्बली में यह बात कही कि प्राइम मिनिस्टर ने एस०वाई०एल० के पानी के मामले को दोबारा सुनने के लिए केसरी-ओपन कर दिया है। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि यह बात कहां तक ठीक है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एस०वाई०एल० के पानी के बारे में एक प्राइवेट मैम्बर रैजोल्यूशन आया हुआ है और

इसको चौधरी साहब ने ही मूव किया हुआ है और इस पर 8 तारीख को भी बहस होनी मुकर्रर हुई है। उस दिन मुझे इसका जवाब देना है। अगर सदस्य चाहे तो उस दिन वृत्तान्त से इस विषय पर जवाब दे दूंगा। जवाब तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अगर अब चाहे तो अब दे सकता हूं।

Mr. Speaker: I think, it will be very fair that on the 8th March he gives a very detailed reply.

Mandi at Nathusri

***889. Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal to set up a Mandi at Nathusri Chopta in Sirsa District; if so, the time by which it is likely to be set up?

कृषि मंत्री (बिग्रेडियर रण सिंह): हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड सर्वे हो चुका है और उम्मीद है कि नाथूसरी चौपटा में मण्डी बना दी जाएगी।

***1007. **Sh. Devender Sharma:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) The total number of Harijan Chaupals constructed upto 31st January, 1979; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct houses for Harijans in the rural areas; if so, the district wise break-up thereof?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(क) 31-1-79 तक 141 हरिजन चौपालों का निर्माण हो चुका है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के मकान बनाए जाने हों। अपितु यह विभाग हरिजनों को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या भाहरी क्षेत्र में, मकान बनाने के लिए 2,000 रुपये का अनुदान देता है।

श्री जगन नाथ: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि एक चौपाल बनाने के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी और अगर किसी गांव में लोग दो दो, तीन तीन चौपाले बनाना चाहे और अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हो तो उनको सरकार ज्यादा से ज्यादा कितनी कितनी ग्रांट दे सकती है? इसके इलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जहां हरिजनों को चौपाले बनाने के लिए यह धनराशि दी जा रही है वहां बैकवर्ड क्लासिज को भी चौपाले बनाने के लिए धनराशि दी जाएगी?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, सरकार चाहती है कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिए ज्यादा से ज्यादा चौपाले बनाई जाएं, लेकिन यह कोई तय जुदा पालिसी नहीं है कि एक गांव में एक ही चौपाल बनाई जाएगी या गांवों में ही चौपाले बनाई जाएं, भाहरों में न बनाई जाएं। भाहरों में भी

हरिजन लोग रहते हैं और भाहर के आस-पड़ोस के लोग खुद कंट्रिव्यू इन करके श्रमदान देगे तो हम भाहरों में भी बनाने के लिए तैयार हैं। अगर दो मुहलले एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे हुए हैं तो वहां पर दो चौपाल की सहूलियत मिले। बैकवर्ड क्लासिज के लिए जहां तक मैं समझता हूँ, काफी दिक्कत है और आस-पास के लोगों की बाराते ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर गांव की पंचायते मुनासिब समझे गांव वाले कंट्रिव्यू इन करें और इसके साथ ही साथ अपोजी इन पार्टी के सदस्य यजैसे राव साहब हैं, ये मुखालफत न करें तो बैकवर्ड क्लासिज की चौपाले बनाने के लिए हम पैसा देगे।

श्री देवी दास: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि भाहरों में भी चौपाले बनाने का सरकार का कोई प्रोग्राम है, जैसे देहातों में बनाने को प्रोग्राम है?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब आ चुका है।

कामरेडु भांकर लाल: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि अब तक किस किस भाहर में कितनी कितनी चौपालें बनाई गई हैं?

चौधरी देवी लाल: मेरे ख्याल में रोहतक में बन चुकी होगी।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने सवाल का जवाब देते हुए एक हमला सा कर दिया.....

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछे ।

राव बीरेन्द्र सिंह: मेरा सवाल यह है कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए चौपाले बनाने की नीति का अब तक तो सरकार ने एलान नहीं किया था, आज किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह नहीं समझती कि हरिजनों के नाम पर चौपाले बनाने से गांवों में छुआछूत ज्यादा फैलेगी? अगर इस तरह से अनटचेबिलिटी परपैचएअ होबी तो बेहतर नहीं होगा। सरकार के द्वारा गांवों में जो चौपाले बनाई जा रही है वह हरिजनों के लिए ही नहीं, सब के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए ताकि सारा गांव मिलकर उससे फायदा उठाए.....

.....

डा० मंगल सैन: क्या गरीबों के लिए न हों? (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह: क्या आप कौम के हिसाब से चौपाले बनाना चाहते हैं, क्या गांव की आबादी को कौमियत में डिवाइड करना चाहते हैं? (व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: जात-पात फैलाने और गांव की आबादी को डिवाइड करने का जहां तक ताल्लुक है, यह काम तो राव साहब और उनकी पार्टी का है, हमारा नहीं है। हम गरीबों की सहूलतों को देख रहे हैं और जहां तक जरूरी समझते हैं इन लोगों के लिए चौपाले बनवाई जा रही है और इनका फायदा

बैंकवर्ड क्लास वाले भी उठा सकते हैं और स्वर्ण जाति के लोग भी उठा सकते हैं।

स्वामी अग्निवे I: जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि चौपाले बनाई जा रही है और जितना धन गांव वाले इकट्ठा करेंगे उतना अनुदान सरकार देगी, लेकिन मैंने देखा है, कहीं कहीं पर आबादी दो हिस्सों में बंट जाती है, एह हरिजन अलग चौपाल बनाना चाहते हैं तो दूसरों बालमीकि अलग बनाना चाहते हैं इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह धन इकट्ठा करके दे सकें। इस प्रकार की कई जातियां हैं, जैसे सिकलीगर, बाजीगर.....

श्री अध्यक्ष: बैंकवर्ड क्लास के बारे में जवाब दे चुके हैं।
(व्यवधान)

स्वामी अग्निवे I: मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 10 हजार ये लोग इकट्ठा करें तो 10 हजार सरकार देगी, इस कंडीशन को वेव करने के लिए सरकार तैयार है?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा है कि जहां पर कोई जाति धन न देकर श्रमदान देती है वहां पर श्रमदान की इवैल्यूएशन कराके ग्रांट दी जाती है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, चौपाल के लिए 10 हजार रुपये की राशि फिक्स की गई है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई हरिजन दस हजार रुपये से ज्यादा डिपोजिट करा दें तो क्या सरकार भी उतनी ही राशि दे देगी?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, केवल हरिजनों के लिए ही नहीं बल्कि यदि कोई बड़े-बड़े सेठ, साहूकार और बड़े-बड़े मालिकान जो जमीन के हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, वे भी भलाई के काम के लिए दस हजार से बढ़ कर दस लाख भी दे तो सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट दस लाख की दी जाएगी। (तालिया) स्पीकर साहब, राव साहब की इत्तलाह के लिए मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह केवल वायदा ही नहीं है बल्कि असलियत है। अभी कल ही एक सेठ ने जगाधारी में किसी देहात में पौलिटैकनिक खोलने के लिए पांच लाख रुपये देने का एलान किया था। उसे लिए मैंने भी पांच लाख रुपये देने के लिए कहाँ हैं उन्होंने यह भी कहा था कि वे पांच लाख रुपये का और इन्तजम करेंगे। उसके जवाब में मैंने भी यही कहा था कि यदि वे और पांच लाख का प्रबन्ध करेंगे तो सरकार भी करेगी।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ डी०सी० ने जो सर्कुलर जारी किया है कि जिन गांव में हरिजनों की एक चौपाल पहली ही है, वहाँ, दूसरी चौपाल नहीं बनाई जाएगी वह क्या सरकार की हिदायतों के तहत जारी किया गया है जबकि बहुत से गांव के हरिजनों ने पहले ही पैसे जमा करवा दिए हैं?

श्री प्रीत सिंह: हरेक केस को फ़ैक्टस के आधार पर देखा जाएगा। अगर एम०एल०ए० साहब के नोटिस में ऐसा कोई

केस है, जहां दूसरी चौपाल की बहुत जरूरत है तो वे हमारे नोटिस में लाए, वहां दूसरी चौपाल बनाने की जरूर इजाजत दी जाएगी।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैचिंग ग्रांट आदि सहित इकट्ठे हुए पैसे को खर्च करने के लिए क्या कोई हरिजनों की कमेटी बनाई जाती है या पंचायत खर्च करती है? (विधन)

श्री प्रीत सिंह: एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें बी०डी०ओ०, सरपंच और पंचायत का एक हरिजन मैम्बर शामिल होता है।

श्री सुमेर चन्द भट्ट: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने मैचिंग ग्रांट के बारे में अभी जो ब्लैकट अ योरेंस दी है उसके बारे में उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका सम्बन्ध क्या हरिजनों की चौपाल से ही है या गांव के दूसरे भलाई के कामों से भी है?

चौधरी देवी लाल: मैं यह बात पहले ही साफ कर चुका हूं। मैंने अपने जवाब में पौलीटैकनिग का रैफरेंस भी दिया था लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि हर किसी काम के लिए जो लोगों की भलाई के लिए हो, सरकार मैचिंग ग्रांट देगी।

राव बीरेन्द्र सिंह: क्या मुख्य मंत्री जी बतायेगे कि इन हरिजन चौपालों की देखभाल के लिए चेयरमैन मुकर्रर किए जाएंगे?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, हरिजनों की चौपाल का फाउंडे इन स्टोन रखने की ड्यूटी एम०एल०एज० की लगाई गई थी लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ड्यूटी को भी राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कबूल नहीं किया।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आन ए पर्सनल एक्सप्लेने इन, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। (विधन)

चौधरी खुर गिद अहमद: इस समय नहीं। This can be done after the question Hour.

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पूरा सहयोग दिया है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के नाम का पत्थर नहीं रखा, यह कसूर जरूर है।

चौधरी देवी लाल: यह राव साहब की बद-किस्मती है कि लोगों ने देवी लाल के नाम से पत्थर रख दिया, यह मेरे अख्तियार की बात नहीं है।

तारांकित प्र न संख्या 942

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Sarsa Bridge

***950. Sarder Tara Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the date on which the construction of Sarsa Bridge in Kurushetra District was sanctioned and the time by which it is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): सारसा डिस्ट्रीक्ट की बुर्जी नं० 23700 पर पुल भवन तथा सड़कें विभाग, हरियाणा द्वारा बनाया जाना है और इसी वर्ष में पूर्ण किया जाना है। सरस्वती फीडर की बुर्जी नं० 36225 पर एक पुल 1975 से 10 साला फेज्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत है और सिंचाई विभाग द्वारा 31-7-79 तक पूर्ण किया जाना है।

Declaration of Backward area

***979. Sh. Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Revenue be pleased to state wheter there is any proposal under consideration of the government of declare the tehsills of Palwal, Nuh and Ferozepur Jhirka in District Gurgaon as backward areas?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका तथा पलवल तहसील के 21 गांवों को पहले ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि तहसील पलवल, नूह तथा फिरोजपुर झिरका के 21 गांव को बैकवर्ड करार दिया हुआ है। लेकिन मैं उनसे जानना

चाहता हूँ कि पलवल तहसील के बाकी गांव की जिनकी हालत वाक्या ही बहुत खस्ता है, बैक वर्ड करार देने में क्या आपत्ति है?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्सड है। जो गांव इस क्राइटेरिया की जद में आते हैं, उन्ही को ही बैकवर्ड करार दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: मेरा सुझाव है कि आप मंत्री महोदय से अलग से मिल लें। वे आपको सारी बात समझा देगे। अभी इन्होंने जवाब दे दिया है कि सरकार ने सारी बात ऐगजामिन करके 21 गांव को बैकवर्ड क्षेत्र घोशित किया हुआ है।

स्वामी आदित्यवे I: क्या मंत्री जी बतायेगी कि वे इस क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड घोशित करेगे?

श्री प्रीत सिंह: यह सैपरेट क्वै चन हैं इस प्र न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, नारायणगढ़ काफी समय तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने हम लोगों के साथ बड़ा अन्याया किया और इस क्षेत्र को फारवर्ड घोशित कर दिया। क्या जनता पार्टी की यह सरकार दोबारा इस क्षेत्र को बैकवर्ड घोशित करेगी?

श्री प्रीत सिंह: नारायणगढ़ पहले से ही बैकवर्ड है।

Amount of loan advanced by the Cooperation Department

***1039. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister of Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) The total amount of loan advanced by the Cooperative Department

(b) The total amount of loan out of that referred to in para (a) above recovered up to 31-1-1979; and

(c) The total number of defaulters above Rs. 1,00,000 (One Lac) in the State as on 31-1-1979?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) सहकारिता विभाग द्वारा व्यक्तिगत ऋणी को सीधे कोई ऋण नहीं दिया जाता। 1-7-78 से 31-1-79 तक 9403.96 लाख रुपये की राशि के अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए हैं।

(ख) उपरोक्त समय में दिया गया ऋण 28 फरवरी और उसके बाद देय होगा परन्तु 1-7-78 से 31-1-79 तक अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों की कुल राशि में से 6996.11 लाख रुपये की राशि वसूली हुई है। 25-1-79 की 9625.15 लाख रुपये के ऋण खड़े थे उनमें से 1534.57 लाख रुपये की राशि अतिदेय थी। जहां तक दीर्घकालीन ऋणों की वसूली का सम्बन्ध है 31-12-78 को 859.77 लाख रुपये की देय राशि में से 619.45 लाख रुपये की वसूली 31-1-79 तक हुई है।

(ग) भून्य ।

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मैने अपने सवाल के पार्ट 'सी' में यह पूछा था कि हरियाणा के अन्दर एक लाख रूपये से ऊपर के कितने डिफाल्टर्ज है और मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि कोई नहीं। क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि बेनामी लोन भी इसमें शामिल है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें सारा लोन आ गया है बेनामी लोन की जो भी िाकायत हमें मिलती है उसकी हम इंकवायरी करते हैं इस ताह की अगर कोई बात माननीय सदस्य के नोटिस में हो तो वे उसे मेरे नोटिस में लाए, उसकी जांच करवाई जाएगी।

श्री फतेह चन्द विंज: क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन सोसाइटियों के जिम्मे पिछला लोन बकाया था उन्हें दुबारा लोन दिया गया या नहीं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जो सोसाइटीज डिफाल्टर हो जाती है, उनको लोन नहीं दिया जाता है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक कोआप्रेटिव सोसाइटीज को लोन देता है उसका प्रोडक्टिव पर्पज जीरो है, इसको कैसे उठाया जायेगा?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सहकारिता आंदोलन से जितना लोगों को भला हुआ है, इससे ज्यादा और किसी भी स्कीम से नहीं हुआ है लोन देने में सब से ज्यादा हाथ कोआप्रेटिव महकमे का है। कोआप्रेटिव सोसाइटीज की तरफ से किसान को खाद, बीज, कीटना तक दवाइयां दी जाती है।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज डिफाल्टर हो गई है और नई वहां पर बनी नहीं है तो उन सोसाइटीज को किस तरह से लिफ्ट देंगे? दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा कौन से ऐस स्टैप्स लिय जा रहे हैं जिनसे इन बैंकों के थू देहात वालों को फायदा दे सकेगे? इस बारे में गवर्नमेंट को लिखा भी चुका हूं।

चौधरी भजन लाल: एक सोसायटी के काफी मैम्बर होते हैं। जिन मैम्बर्ज की तरफ काफी रूपया खड़ा है, उन सोसाइटीज को खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से कोई लोन नहीं दिया जायेगा। जिन लोगों ने सोसाइटीज का सारा पैसा दे दिया है, वे अपनी नई सोसायटी बना सकते हैं गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है सरकारी बैंक उन सोसायटीज को लोन देंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1021

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य चौधरी राम किान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

**Stock of medicines in Dispensary in the Haryana M.L.As'
Hostel**

***1003. Ch. Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) Whether the stock of medicines is complete in the Dispensary located in the Haryana M.L.As' Hotel;

(b) Whether any complaint regarding the non-availability of medicines in the said dispensary has been received by the Medical Officer of Chief Medical Officer, Ambala; and

(c) If so, the action taken so far by the Government thereon?

Health Minister (Smt. Dr. Kamal Verma):

(a) The dispensary at Haryana M.L.A. Hostel was started to provide essential and emergency medicines to the M.L.As. Adequate quantities of essential and emergency medicines are available in the dispensary.

(b) A suggestion was received that the medicines other than the emergency and essential medicines should also be provided in the dispensary on demand.

(c) The suggestion has been accepted and necessary instructions have been issued.

चौधरी उदय सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि एम०एल०एज० होस्टल की डिस्पैन्सरी में

दवाइयों का प्रबन्ध किया हुआ है। लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूँ कि क्या कोई एम०एल०ए० खड़ा हो कर यहां हाउस में कह सकता है कि वहां पर दवाइयां पूरी मिलती है? और डाक्टर को भी इख्तियार नहीं है कि वह एम०एल०ए० के लिए दवाई खरीद सके। एम०एल०ए० को दवाई खरीदने के लिए कन्ज्यूमर स्टोरज पर जाना पड़ता है। चार रूपये की दवाई होती है और दस रूपये स्कूटर वाला चार्ज कर लेता है। दवाई स्टोर से खरीद भी ली जाये तो उसका पैसा वापिस लेने के लिए सी०एम०ओ० अम्बाला से काउन्टर साइन कराने पड़ते हैं। इस तरह से बहुत परे ानी का सामना करना पड़ता है तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने दिनों तक यह समस्या हल हो जायेगी?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: इस समस्या को हल करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आर्डर जारी हो चुके हैं। डाक्टर को कह दिया गया है कि अगर किसी एम०एल०ए० के लिए दवाई चाहिए तो वह स्वयं दवाई ला कर दें।

डा० बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, पंजाब एम०एल०एज० होस्टल में जो डिस्पेंसरी खुली हुई है, उसमें दांतों को चैक करने का इन्तजाम भी है तब वहां एक छोटी सी टैस्टिंग लेब्राटरी भी है। इसी तरह से हमारे एम०एल०एज० होस्टल में भी उसकी मांग की गई परन्तु फाइनेंस की कमी होने की वजह से वह मांग रिजैक्ट कर दी गई है तो मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना

चाहता हूँ कि इस छोटी सी लैब्रोटरी को सैकड़ों न करने का क्या कारण है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: इस बारे में तो वित्त मंत्री महोदय ही बता सकते हैं कि क्यों रिजैक्ट की है। हमने दो बार पहले केस भेजा था और अब तीसरी बार भेज रहे हैं। इस बार हमें आशा है कि वित्त मंत्रालय से जरूर स्वीकृति मिल जायेगी।

चौधरी खुरशद अहमद: स्पीकर साहब जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर महोदय ने हाउस में जवाब दिया है उसको सुन कर क्या मैं आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर महोदय से पूछ सकता हूँ कि वे तीसरी बार इस डिमान्ड को स्वीकार कर लेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): स्पीकर साहब, मुझे तो इसके लिए नोटिस चाहिए। (हंसी).....

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपका जरिए हाउस के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ कि एक एम०एल०ए० कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है लेकिन उनके लिए भी बजट में इतना थोड़ा पैसा दवाइयों के लिए रखा जाता है। इसको क्यों नहीं बढ़ाया जाता है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय आम डिस्पेंसरी में छः हजार की दवाइयाँ देने का प्रबन्ध है परन्तु एम०एल०ए० डिस्पेंसरी के लिए 14 हजार की दवाइयाँ फरवरी मास तक खरीदी

जा चुकी है। इसक इलावा आव यकतानुसार और भी ज्यादा खर्च करने की इजाजत दे दी है।

चौधरी भले राम: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेगी कि एम०एल०एज० को ही दवाइयं दी जाती है या दूसरे लोगों को भी दी जाती है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: केवल एम०एल०एज० के लिए ही यह डिसपैसरी है अगर ऐसी कोई बात है तो उसक बारें में देख लेंगे कि अन्य आदमी वहां से दवाई न लें।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई ऐसा मौका हो जाये कि किसी पब्लिक के आदमी को मैडिकल एड की आव यकता पड़ जाये तो एमरजेंसी में डाक्टर का भी यह फर्ज होता है कि वह उसको अटैन्ड करे।

Water logging around Khetri Minor

***905 Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) Whether it is fact that the problem of water logging subsists in the area around the syphon on the Khetri Minor; and

(b) If so, the details of the steps proposed to be taken to combat the water logging in the said area together with the time by which these are likely to be taken?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):

(अ) नहीं, ऐसा कोई माईनर नहीं है।

(ब) उक्त 'ए' के सम्मुख प्र न ही नहीं उठता।

स्वामी आदित्यवे I: स्पीकर साहब, यह वही माईनर है जो पलवल तहसील में है जिसके सम्बन्ध में 15 जनवरी को घोषित किया गया था। यह वाटर लोगिंग एरिया हैं तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि उसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री अध्यक्ष: गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करके जवाब दिया है। इस नाम की कोई माईनर नहीं है।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, यह खतेला गांव के नजदीक हैं खतेला माईनर में साइफन गलत बना हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, खेतरी माइनर कोई नहीं है। खतेला माइनर है।

स्वामी आदित्य वे I: अध्यक्ष महोदय, यह मेरी गलती नहीं है। यह सचिवालय की गलती है। मेरे मूल प्र न को निकाल कर देखा जाये, उसमें सही लिखा है।

श्री अध्यक्ष: आप इसको, अमेंड करके एज अन-स्टार्ड क्वै चन दे दें तो मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे देंगे।

Enrolment with the Employment Exchanges

***882 Sh. Shamsheer Singh:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) The number of persons possessing Matric, Graduate, Post-Graduate, Technical, JBT and B.Ed qualifaication registered with the Employment Exchanges in the State as on 31-3-1978;

(b) The total number of persons out of those referred to in part (a) above who have been provided with jobs; and

(c) The total number of persons, category-wise, as referred to in part (a) above who are still on the waiting list for employment as on 31-2-1978 in the State?

सहकारित एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क), (ख) तथा (ग): अपेक्षित सूचना विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणिका

(क) 30-6-78 हरियाणा में रोजगार कार्यालयों के संजीव रजिस्टर पर रहे निम्नलिखित क्षेत्रीय क प्रार्थियों की संख्या इस प्रकार से है:-

क्रंमाक	कैटेगरी	30-6-78 को हरियाणा में रोजगार कार्यालय के संजीव रजिस्टर पर संख्या
1.	मैट्रिक	94366

2.	स्नातक	29728
3.	स्नातकोत्तर	3642
4.	तकनीकी	8714
5.	जे०बी०टी०	8618
6.	बी०एड०	10115

नोट:- ऊपर दी गई कैटेगरी के प्रार्थियों सम्बन्ध 31.3.78 के आंकड़े अपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह आंकड़े अर्ध-वार्षिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं अतः 30-6-78 से सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं।

(ख) 30-6-78 को समाप्त हुये अर्ध-वर्ष में नौकरी पर लगे प्रार्थियों के आंकड़े भाग 'क' की कैटेगरी के अनुसार नीचे दिये जाते हैं:-

क्रमांक	कैटेगरी	30-6-78 को समाप्त हुये अर्ध वर्ष में नौकरी पर लगे प्रार्थियों की संख्या
1	2	3

1.	मैट्रिक	5021
2.	स्नातक	2344
3.	स्नातकोत्तर	256
4.	तकनीकी	480
5.	जे०बी०टी०	2369
6.	बी०एड०	1484

(ग) 31-12-78 को राज्य के रोजगार कार्यालयों से संजीव रजिस्टर पर रहे प्रार्थियों की संख्या कैटेगरी के अनुसार इस प्रकार है:-

क्रमांक	कैटेगरी	31-12-78 को को संजीव रजिस्टर पर प्रार्थियों की संख्या
1.	मैट्रिक	90503
2.	स्नातक	28791
3.	स्नातकोत्तर	4581
4.	तकनीकी	8487

5.	जे०बी०टी०	6223
6.	बी०एड०	9957
<p>नोट:— इन आंकड़ों में उन व्यक्तियों को नाम भी सम्मिलित है जिनके नाम 1-7-78 से 31-12-78 तक की अवधि में दर्ज किये गये ।</p>		

श्री भाम ेर सिंह: मिनिस्टर महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'सी' में बताया है कि 31-12-78 तक मैट्रिक 90503 ग्रेजुएट्स 28791 पोस्ट ग्रेजुएट्स 4581 टैक्नीकल 8487, जे०बी०टी० 6223 और बी०एड० 9957 बेरोजगार है। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि इन्हें नौकरी देने का कोई स्पैसिफाईड टाईम मुकर्रर किया है कि इतने टाईम तक नौकरियाँ दे दी जायेगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले भी सदन में बताया गया है कि सबको नौकरी देना तो कठिन है क्योंकि हर साल 20-22 हजार लोगों को नौकरियाँ दी जाती है और अगले ही साल एक लाख पढ़े-लिखे युवक और आ गजते है ते इस समस्या का समाधान होना तो मुि कल है लेकिन हमारी सरकार ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि वे

गांवों में उद्योग धंधे लगाये। दस हजार से 1 लाख रूपये तक लोन देगें और उसमें 15 परसैन्ट तक सबसिडी भी दी जायेगी। इस तरह से पांच साल तक टैक्स में छूट दी जायेगी जिससे नौजवान नौकरी की तरफ नहीं जायेगे और वे अपने पांव पर खड़े हा सकेंगे।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ में जो डेरी प्लान्ट काफी दिनों से तैयार हो रहा है....

श्री अध्यक्ष: गया लाल जी, यह प्र न डेरी से सम्बन्धित नहीं है.....

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी-अभी यह बताया कि पढ़-लिखे लोगों को इतनी नौकरियां तो वे नहीं दे सकते, वे उन्हें उद्योग धन्धे लगाने के लिये कह रहे हैं। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योग खोलने की स्कीम के तहत अब तक उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिलाया है?

श्री अध्यक्ष: यह तो एक सैपरैट सवाल है, इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार की यह योजना है कि पढ़-लिखे लोग उद्योग धन्धे लगाये क्योंकि वह इतने रोजगार तो दे नहीं सकते।

मै आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज का क्या बनेगा? क्या इन एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज को उद्योग-धन्धों में मददगार बनाने की कोई प्रोपोजल है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जहां तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज का ताल्लुक है, जैसे मैंने बताया है वे हर साल 20-22 हजार लोगों को नौकरियां दिलाने में मदद कर रहे हैं।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: जैसे कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हम सब को नौकरियां नहीं दे सकते, क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करने के लिये तैयार है कि जो बी०एड० और जे०बी०टी० की ट्रेनिंग है, इसको बन्द कर दिया जाये?

Mr. Speaker: This is a separate question.

स्वामी अग्निवे 1: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि हमारे प्रदेश में नौकरियों के मामले में और खास कर सहकारी बैंकों में रोजगार दिलाने के बारे में काफी रिक्त चलती है? मैं उन्हें बताता हूँ कि इन बैंकों में मिनी बैंक के मैनेजर लगाने के लिये 8-8 हजार रूपया देना पड़ता है, क्या वे इस तरफ से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसे समाप्त करने का कोई विचार रखते हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने और पोहलू साहब ने भी बैंकों की नौकरियों में कुरूपान का जिक्र किया है। पोहलू साहब ने कुरुक्षेत्र बैंक के बारे में कहा था लेकिन आज तक न तो पोहलू साहब ने ही और न स्वामी जी ने ही कुछ लिखकर दिया है। अगर कोई स्पैसिफिक इन्स्टांस दे कि फलां आदमी से पैसे लिये गये तो हम बाकायदा उसकी इन्क्वायरी करवायेगे और उसमें चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इन्वाल्ड हो, किसी को भी माफ! नही किया जायेगा।

श्री बेलदेव तायल: स्पीकर साहब मै मंत्री महोदय से केवल इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि जो नौकरियां दी जाती है, जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक लाख व्यक्तियों में से केवल 20-22 हजार आदमियों को ही आप नौकरी दे पाते है उन नौकरियों को देने का मापदण्ड क्या होता है? क्या उनका मापदण्ड मैरिट है, योग्यताएं है या सिफारि है या कुछ और है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कोर्ि है तो यही होती है कि योग्यता के आधार पर ही नौकरियां दी जाये और दी भी जाती है। लेकिन कई बार एम०एल०ए० साहेबान जो यहां पर सवाल पूछ रहे है। आकर यह कहते है कि नही, इस लड़के को लेना है, चाहे उसमें योग्यता है या नही है। यह मेरा लड़का तो हर हालत में लगना चाहिए।

Hospital at Sirsa

***890 Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for Hospital at Sirsa; if so, the time by which the construction work is likely to be taken in hand?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमल वर्मा): हां, धन उपलब्धि होने पर जरूरत हस्पताल सिरसा के लिये नए भवन का निर्माण वर्ष 1979-80 में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

चौधरी जगदी 1 कुमार बैनीवाल: स्पीकर साहब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या धन कभी उपलब्ध भी होगा या नहीं?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: होगा, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया है, यह प्रोपोजल अन्डर कन्सीड्रे 1न है।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि धन उपलब्ध होने की कोई सीमा भी रहेगी या नहीं कि कब तक धन उपलब्ध हो जायेगा?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: जरूर रहेगी, हमने अपनी पांच साल प्लान के पहले साल में ही इसकी योजना का प्रस्ताव रखा हुआ है।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि धन की उपलब्धि होने के पचात् कौन-कौन सी जगह अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है?

श्री अध्यक्ष: सवाल तो अलग है, लेकिन अगर मंत्री महोदया चाहे तो जवाब दे सकती है।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के सम्बन्ध में पूछ रही है या सब डिवीजनल लैवल पर? मैं तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरज का ही बता सकती हूँ।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मैं तो बावत का पूछ रही हूँ।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: वहां पर होगा।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं वजीर साहिबा से यह पूछना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में अस्पताल की बिल्डिंग आलरैडी बनी हुई है और उसका पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा है, क्या उसका पूरा इस्तेमाल किये जाने की कोई प्रोपोजल है अगर है तो उसे कब तक इस्तेमाल किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: पूरे इस्तेमाल से आपका क्या मतलब है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं इनका मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ। इनका मतलब यह है कि कुरुक्षेत्र में जो अस्पताल की बिल्डिंग है वह 100 बैड्स के लिये है

लेकिन वहां पर अभी 50 बैड्स ही हैं। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि वह अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और ज्यो-ज्यो फाईनैसिज की पोजीशन ठीक होती जायेगी त्यों-त्यों हम इस बारे में प्रबन्ध करते जायेगे।

श्री देवेन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय क्या इसके लिये सरकार कोई टाइम लिमिट फिक्स करने के लिए तैयार है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पहले तो उस इलाके के अन्दर जहां पर अस्पताल बिल्कुल भी नहीं है अस्पताल देंगे। जहां पर आलरैडी एगजिस्ट करते हैं, उनको अपग्रेड करने की बात तो बाद में सोचेगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि कई बार अस्पतालों में मरीज के साथ दूसरे आदमी का रहना जरूरी हो जाता है लेकिन उसके ठहरने के लिए आम तौर पर अस्पतालों में कोई जगह नहीं होती है। क्या अस्पतालों के पास ही कोई उनके ठहरने के लिये सुविधा प्रदान करने की बात सरकार सोचेगी ?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अभी लोगों की भलाई के लिये एक प्रस्ताव रखा है कि वहां के लोग अगर चाहे तो पैसा इकट्ठा करें, सरकार भी उतनी ही मैचिंग ग्रांट देगी। इस तरह से अगर लोग चाहें तो किया जा सकता है।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि हांसी का जो प्रोपोजड अस्पताल है, उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर पायेगे?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसक लिये टैन्डर काल कर लिये गये है। भीघ्र ही काम भुरू हो जायेगा।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जहां पर 15-15 और 17-17 किलोमीटर तक कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है, वहां पर कोई सब सेंटर खोलने की सरकार की स्कीम है?

श्रीमती डा० कमला वर्मा: हां जी। अध्यक्ष महोदय, यह तो कई बार कहा जा चुका है कि लोगों की जरूरत को नजर में रखते हुए वहां पर प्रायेरिटी दी जायेगी।

Trades in the Industrial Training Institutes

***1071. Sh. Devender Sharma:** Will the Minister for Industgries be pleased to state—

(a) Whether there is any trade of Hand-Composing-Cum Proof reading/Printing Machine Operators/Binding in the Industrial Training Institutions In Haryana State; if so, in which I.T.I. and since when;

(b) The number of persons imparted training in the above said trades during the year;

(c) The steps being taken to give publicity to the benefits of the above said trades;

(d) Whether any representation was received from the owners/associations of Printing Press in Haryana State regarding

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

Reservation of posts for Ex-servicemen in Haryana

***941. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister be pleased to state—

(a) The quota of posts reserved in class I, II and III posts for ex-servicemen in the state of Haryana, at present;

(b) Whether the reserved posts as mentioned in part (a) above have been filled by the ex-servicemen at present; if not, the reasons therefore; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase quota in reservation of posts for the ex-servicemen in class I, II and III. if so, the time by which it is likely to be increased?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) हरियाणा राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी I तथा II पदों/रिक्तियों में 5 प्रति 100 तथा श्रेणी III के पदों/रिक्तियों में 25 प्रति 100 आरक्षण किया गया है।

(बी) अद्यतन उपलब्ध सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है। आरक्षित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों की कम भर्ती का कारण यह है कि वांछित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले भूतपूर्व सैनिक काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

(सी) नहीं।

विवरणिका

हरियाणा राज्य के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या देखते हुए विवरणी-31-3-77 की विवरण स्थिति अनुसार:-

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिशतता
श्रेणी I	875	19	2.2
श्रेणी II	3,231	37	1.1
श्रेणी III	1,17,280	3855	3.3
श्रेणी IV	28,223	1877	6.7

जोड़	1,49,609	5788	3.9
------	----------	------	-----

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो जगह खाली पड़ी है उनको कब तक भर लिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि जगह खाली पड़ी हुई है लेकिन सफिसेंट ऐक्सीपीरीसेंस और क्वालिफिके ान्ज वाले आदमी नहीं आ रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब वेकेन्सी ऐडवरटाइज होती है और भरी जाती है और सही क्वालिफिके ाज के फौजी नहीं आते हैं, क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन रिजर्वड कोटै की वेकेन्सीज को होल्ड ओवर किया जाता है या दूसरी कैटेगरीज से भर ली जाती है?

चौधरी देवी लाल: जितनी काबलियत या क्वालिफिके ांज की जरूरत होती है अगर उस क्वालिफिके ांज का आदमी नहीं मिलता तो वह पोस्ट खाली नहीं रखी जाती थी और उसको भर लिया जाता था लेकिन 20.08.1978 को एकस सोलजर्ज सेलर्ज एण्ड एयरमैन बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि ट्रेनिंग सैन्टर्ज खोले जाएं जिनमें इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए ताकि यह कमी पूरी की जा सके।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, उसमें तो क्वालिफिके इन कम नहीं की जा सकती है क्योंकि कुछ इस किस्म की कैटेगरीज है जैसे टाईपिस्ट चाहिए और क्वालिफिके इन कम करें तो काम ठीक से नहीं हो सकेगा। इसी तरह से वेक्सीनेटर है अगर उसकी क्वालिफिके इन कम कर दें तो टीका ठीक से नहीं लग पाएगा। इसी तरह से स्टेनों टापिस्ट है। इस किस्म की कमी को दूर करने के लिये हमने उसकी सर्विस खत्म होने से एक साल पहले आन दि जौब प्री रिलीज ट्रेनिंग स्कीम तैयार की है जिसमें इस स्कीम की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यह कमी पूरी हो सके।

Tubewells in the state

***1035. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The district wise number of Irrigation tube wells which have been installed by the Government in the State during the period from 4-7-1978 to 31-1-1979;

(b) The total number of tube wells in the State as on 31-1-1979;

(c) the total number of tubewells out of those referred to in part (b) above which are in working order at present; and

(d) The number of irrigation tube wells which are proposed to be installed up to 31-3-1979 in each district and each Assembly Constituency in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):-

(क) जिला	नलकूपों की संख्या
अम्बाला	14
सिरसा	1
गुडगांव	5
	20
(ख)	2425 नं०
(ग)	2233 नं०

(घ) जिला	विधान सभा हल्का	नलकूपों की संख्या
अम्बाला	नारायणगढ़	17
	सढ़ौरा	4
	अम्बाला	3
	बराड़ा	3
गुडगांव	फरीदाबाद	7

	पलवल	3
सिरसा	रोड़ी	30
सिरसा	ऐलनाबाद	12
भिवानी	लोहारू	5
	कुल जोड़	84

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीयुएँसी जगाधारी में थोड़ा सा इलाका ऐसा है जहां पर ट्यूबवैल काफी गहरे लगते हैं और वहां पर प्राइवेट आदमी और मीन के ट्यूबवैल नहीं लगा सकता, बोर नहीं कर सकता हैं यह कलावाड़ के साथ का इलाका है जहां पर पानी काफी गहरा हैं बाकी तो भगवान की कृपा है। कि अम्बाला जिला में काफी पानी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस इलाकें में एक दो ट्यूबवैल लगाने की कृपा की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसको एग्जामिन करवा लेगे और अगर लगने की सम्भावना होगी तो लगवा देगे।

Transfer of Teachers

***1022. Ch. Ram Krishan:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that teachers belonging to Safidon constituency have been posted in the schools of District Kurukshetra;

(b) Whether it is also a fact that Teachers belonging to Sonapat District have been posted in Safidon Constituency; and

(c) If so, whether Government intends to transfer the said teachers to their home District, if not, the reasons therefor?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, श्री रामकिान जी का जो सवाल है वह पिछले दिनों जो जे०बी०टी० टीचर्स की सिलेक्शन हुई है उससे सम्बन्धित हैं उस सिलेक्शन में जींद जिले के लिये 236 स्थानों के लिये नाम रिक्त रखे गये थे तो इसलिये सोनीपत के आदमियों को सफ़ीदों में भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपस में मिल कर म्यूचुअल ट्रांसफर की कोई बात हागी तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

चौधरी राम किान: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में केवल यह कह कर टाल दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उनके इस जवाब को चैलेंज करता हूँ कि मेरी कांस्टीचुएँसी के अन्दर कब भी सोनीपत के 30-35 जे०बी०टी० और बी०एड० टीचर्स लग हुए हैं लेकिन इन्होंने अपने जवाब में कह दिया है कि कोई नहीं है। यह गलत कह रहे हैं यूँ ही हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा पास जो सूचना थी, वह मैंने इस हाउस के सामने रख दी है। अगर आनरेबल मैम्बर के पास कोई ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो वह मुझे लिखकर भिजवा दें, मैं इंकवायरी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आनरेबल मैम्बर को सुजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई नाम उनके पास हो तो वह लिखकर आनरेबल मिनिस्टर साहब के पास भिजवा देवे, और मुझे पक्की उम्मीद है कि आनरेबल मिनिस्टर उस पर जरूरी कार्यवाही करेगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या कल इस सवाल पर सप्लीमेंटरी हो जाएंगी।

Mr. Speaker: कल के लिए, there is not rule to carry over the supplementaries इस सवाल का जवाब आ चुका है।

नियम 45 अे अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

***1004 Ch. Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to bring the grades of D.S.Ps. at par with H.C.S. Officers?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उप पुलिस अधीक्षकों के वेतनमाना संशोधित करने के लिये प्रस्ताव पर

सरकार द्वारा विचार किया गया था और और निर्णय लिया गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाए।

Subsidy of Farmers

***1052. Ch. Har Swarup Bura:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant subsidy to the Farmers who get their water courses lined; if so, the amount of subsidy proposed to be given to them?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): मोगे के चक के सारे भागीदारों को खालों के पक्क करने के खर्च पर सहायता करने की कोई प्रयोजना नहीं है किन्तु लघु तथा सीमांतक किसानों को एस०एफ०डी०ए० तथा एम०एफ०ए०एल० वाले खण्डों में तथा इनके इलावा उन खण्डों में जहां एस०एफ०डी०ए० आदि का प्रोग्राम अभी तक लागू नहीं, वहां सहायता की प्रयोजना है।

भारत सरकार की एस०एफ०डी०ए० तथा एम०एफ०ए०एल० के बिना खण्डों में लघु तथा सीमांतक किसानों से वसूली होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत सहायता देने की प्रयोजना है।

जूई उठाना सिंचाई योजना के क्षेत्र में एस०एफ०डी०ए० तथा एम०एफ०ए०एल० से मिलने वाली मदद से अलावा सी०ए०डी०ए० ने 10 खालों पर सारे भागीदारों को विशेष रूप से

सहायता दी है। भविष्य में यह सहायता केवल लघु तथा सीमांतक किसानों तक ही सीमित रखी जायेगी।

अतारांकित प्र न उत्तर

Country liquor and Indian make Foreign liquor shops

240. Swami Adityavesh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) The total number of vends of country liquor and Indian made foreign liquor shops at present in the state;

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to close the Indian made foreign liquor shops in the State; and

(c) If so, the details thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) (i) देसी भाराब की दुकानें	312-13 थोक की दुकानों सहित
(ii) भारत में बनी विदे पी भाराब (आई०एम०एफ०एल०) की दुकानें	497-45 थोक की दुकानों सहित
(बी तथा सी) वर्ष 1979-80 में भारत में बनी विदे पी भाराब की 40 प्रति 100 दुकानों को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।	

Allotment of Nazool Land

241. Swami Adityavesh: will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether the lease holders of the Nazool for Revenue be pleased to state—

(a) Whether the Nazool land is auctioned by the Government in open auction?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) नजूल भूमियां दो प्रकार की होती हैं। एक नजूल भूमि (एसचीटिड) तथा दूसरी भूमि (नान-एसचीटिड)। नजूल भूमि (एसचीटिड) लैंड (हस्तांतरण) नियम, 1956 के अधीन केवल अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को अलाट की जाती है। अलाटमेंट के सम्बन्ध में इन जातियों के पट्टेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। रिहायगी प्लॉट खुली बोली द्वारा बेचे जाते हैं।

(बी) जैसा कि ऊपर (ए) के अधीन बताया जा चुका है। कि नजूल भूमि (एसचीटिड) का नीलामी द्वारा निपटाना नहीं किया जाता है। नजूल भूमि (नान-एसचीटिड) का निपटान खुली बोली द्वारा अथवा आपसी बातचीत द्वारा किया जाता है। इन भूमियों को निपटान उप मडल स्तर पर सरकार द्वारा गठित नजूल भूमि

(नान-एसचीटिड) निपटाना कमेटियों की सिफारि ा अनुसार किया जाता है ।

Compensation for the construction of Mirka Minor

242. Swami Adityaves: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) Whether the compensation has so far been paid to the farmers in respect of Mirka Minor constructed during the year 1961, in Nuh Tehsil of District Gurgaon; and

(b) If reply to part (a) above be in the negative, the reasons there for and the time by which the compensation is likely to be paid?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(अ) मिर्का माईनर से सम्बन्धित भूमि के मुआवजा की आदायगी की स्थिति निम्नलिखित है:—

कुल मुआवजा अदायगी करने वाली रकम 11615-97 रुपये थी जिसमें से जमींदारों को रुपये 88291-91 को अदायगी 25-1-1962 तथा 1-3-1962 को की गई थी बकाया रुपये 2786-06 की रकम भूमि अभिग्रहरण अधिकारी, अम्बाला के हवाले कर दी गई थी ताकि जो भी जमींदार मुआवजा लेने आवे तो उन्हें अदायगी कर दी जाये। इस बकाया रुपये 2786-06 में से भूमि अभिग्रहरण अधिकारी अम्बाला ने रुपये 2400-11 की रकम जमींदारों को अदा कर दी है। अब केवल 385-95 की राशि

बकाया है जोकि जमींदारों को देनी है। जैसे कि भूमि अभिग्रहण अधिकारी रोहतक ने सूचित किया है कि अभी तक जमींदार उपर्युक्त बकाया रकम को लेने नहीं आए हैं। यह बकाया रकम भूमि अभिग्रहण अधिकारी ने पलवल खजाना में जमा करवा रखी है और अभी तक वही जमा पड़ी है।

(ब) केवल रूपये 385-95 नाम मात्र रकम है जोकि जमींदारों को अब जब भी वे आएंगे उन्हें अदा कर दी जाएगी।

ध्यानकर्षण सूचनाए

(i) उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सम्बन्धी:—

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने कंज्यूमर्ज गुड्ज की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बारे में एक काल अटेन इन मो इन दिया था.....

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of a Call Attention Motion from Sh. Shamsheer Singh Surjeala, M.L.A. concerning the rise in prices of certain consumer goods after the presentation of the Central Budget. I have disallowed it on two counts. Firstly, this is a subject matter for the Central Government and, as such, the Lok Sabha is the proper forum for this subject and not the Haryana Vidhan Sabha. Secondly, Vide Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shukdher page 618, the provision of the Finance Bill relating to the imposition or increase in duties of custom or excise come into force

immediately on the expiry of the day on which the bills is introduced.

श्री भामोर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बजट के खिलाफ कोई एतराज नहीं किया था कजूमर गुड्ज पर जो बजट के बाद कीमते बढ़ी है उन कीमतों को मेनटेन करने के लिये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सैन्ट्रल बजट के कुछ आधारों की वजह से प्राईसिज बढ़ी है जो आपने लिखा है। They come into force with immediate effect.

(i) हरियाणा के डाकखानों में बेनामी जमा राशियों सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of Call Attention Motion from Swami Aditya Vesh, M.L.A. concerning the deposits in benamis in Post Offices in Haryana. I have disallowed the same as it concerns the department of Posts and Telegarph which is a Central Government subject and as such cannot be discussed in the Haryana Vidhan Sabha. Further, a question on this subject has been discussed in the Lok Sabha and, therefore, undoubtedly the Central Government must be seized of the problem.

(iii) टपरीवासियों तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: मुझे सर्वश्री अग्निवे 1, आदित्यवे 1, भांकर लाल, गया लाल जगन नाथ, सुमेरचन्द भट्ट तथा श्रीमती सुशमा स्वराज, एम०एल०एज० की तरफ से टपरीवास तथा विमुक्त जाति को रिजर्व्ड कास्ट की लिस्ट में से निकाल कर रिजर्व्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में शामिल करने और उनको कुछ सहूलियतें देने के बारे में एक ध्यान दिलाओ प्रस्ताव का नोटिस मिला है और मैं उसको मंजूर करता हूँ। स्वामी अग्निवे 1 जी अपने प्रस्ताव का पढ़ दे और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के कल्याण सम्बन्धी मंत्री जी अब अपना ध्यान दे सकते हैं या कुछ समय मांग सकते हैं।

स्वामी अग्निवे 1: अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ने मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के इस आवयक मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह हम सबके लिए बहुत खेद की बात है कि विमुक्त जाति, टपरीवास जैसे पिछड़े वर्ग सदियों से पिछड़े हुए चले आ रहे हैं। इन विमुक्त जातियों का प्रस्ताव नं. 22 सन् 1793 और 1871 के अनुसार विभिन्न कबीलों का नाम देकर जुरायन पे 11 जैसा कठोर कानून लगा दिया गया था और इन जातियों को अपराधी कबीले, नोमेडिक ट्राइब, डिनोटिफाईड ट्राइब सिकलीगर ट्राइब, बाजीगर ट्राइब इत्यादि के नाम से पुकारा गया और इसी प्रकार इन कबीलों

का नाम 31 अगस्त 1952 तक रहा और 31 अगस्त, 1952 तक जुरायन पे गा जैसा कठोर कानून भी लागू रहा।

हरियाणा राज्य में विमुक्त जाति टपरीवास जैसे इतने बड़े वर्ग जिसमें 32 जातियां आती हैं, जैसे सहांसी, बाजीगर, सीकलीगर, कुचबन्दे, नट, डेह भेडकुट, सपेले, बोरिये और सिंगीकार इत्यादि का एक भी एम.एल.ए., एम.पी., आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा एच.सी.एस. अधिकारी नहीं है।

31 अगस्त, 1952 से पहले इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा हुआ था। परन्तु उसके बाद इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रख दिया गया। जिसका लाभ कुछ एक विशेष जातियां ही उठा रही है और इन विमुक्त जातियों को हर क्षेत्र में हानि उठानी पड़ रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 339(2), 15(4), 16(4) और 46 के अनुसार राज्य सरकारों का विमुक्त जाति जैसे पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं देने का अधिकार है। ऊपर लिखित संविधानिक धाराओं और जनता पार्टी के चुनाव घोशणा पत्र और भारत के प्रधान मंत्री व गृह मंत्री के चुनाव घोशणा के अनुसार विमुक्त जातियों जैसे पिछड़े वर्ग को राजनैतिक दिया जाना चाहिए। अतः हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित मांगों को अविलम्ब पूर्ण करने की कृपा करें:-

(1) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि टपरीवास तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में से निकाल कर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

(2) इन जातियों का एक अलग निदेशालय खोला जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो जगह खाली पड़ी हैं उनको कब तक भर लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि जगह खाली पड़ी हुई है लेकिन सफिसेंट ऐक्सपीरियेंस और क्वालिफिकेण्ड वाले आदमी नहीं आ रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब वेकेन्सी ऐडवर्टाइज होती हैं और भरी जाती हैं और सही क्वालिफिकेण्ड के फौजी नहीं आते हैं, क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन रिजर्वड कोटे की वेकेन्सीज को होल्ड ओवर किया जाता है या दूसरी कैटेगरीज से भर ली जाती हैं ?

चौधरी देवी लाल: जितनी काबलियत या क्वालिफिकेण्ड की जरूरत होती है अगर उस क्वालिफिकेण्ड का आदमी नहीं मिलता तो वह पोस्ट खाली नहीं रखी जाती थी और उसको भर लिया जाता था लेकिन 20-8-1978 को एक्स

सोलजर्ज सेलर्ज एण्ड एयरमैन बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि ट्रेनिंग सैन्टर्ज खोले जाएं जिनमें इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए ताकि यह कमी पूरी की जा सके।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो क्वालिफिके ांज उन्होंने रखी हैं और उस क्वालिफिके ांज के आदमी अगर नहीं मिलते हैं तो क्या क्वालिफिके ांज को लिबरल करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, तो क्वालिफिके ांज कम नहीं की जा सकती हैं क्योंकि कुछ इस किस्म की कैटेगरीज हैं जैसे टाईपिस्ट चाहिए और अगर क्वालिफिके ांज कम करें तो काम ठीक से नहीं हो सकेगा। इसी तरह से वेक्सीनेटर है अगर उसकी क्वालिफिके ांज कम कर दें तो टीका ठीक से नहीं लगा पाएगा। इसी तरह से स्टेनो टाईपिस्ट हैं। इस किस्म की कमी को दूर करने के लिए हमने उसकी सर्विस खत्म होने से एक साल पहले आन दि जॉब प्री रिलीज ट्रेनिंग स्कीम तैयार की है जिसमें इस स्कीम की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यह कमी पूरी हो सके।

Tubewells in the State

***1035. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the district wise number of Irrigation tubewells which have been installed by the Government in the State during the period from 4-7-1978 to 31-1-1979;

(b) the total number of tubewells in the State as on 31-1-1979;

(c) the total number of tube wells out of those referred to in part (b) above which are in working order at present; and

(d) the number of irrigation tube wells which are proposed to be installed upto 31-3-1979 in each district and each Assembly Constituency in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जिला	नलकूपों की संख्या
अम्बाला	14
सिरसा	1
गुडगांव	5
कुल जोड़	20

(ख) 2425 नं.

(ग) 2233 नं.

(घ)

जिला	विधान सभा हल्का	नलकूपों की संख्या
अम्बाला	नारायणगढ़	17
	सढौरा	4
	अम्बाला	3
	बराड़ा	3
गुड़गांव	फरीदाबाद	7
	पलवल	3
सिरसा	रोड़ी	30
सिरसा	ऐलनाबाद	12
भिवानी	लोहारू	5
	कुल जोड़	84

डा. बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीचुएँसी जगाधरी में थोड़ा सा इलाका ऐसा है जहां पर ट्यूबवैल काफी गहरे लगते हैं और वहां पर प्राईवेट आदमी बगैर मीन के ट्यूबवैल नहीं लगा सकता, बोर नहीं कर सकता है। यह कलावड़ के साथ का इलाका है जहां पर पानी काफी गहरा है बाकी तो

भगवान की कृपा है कि अम्बाला जिला में काफी पानी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस इलाके में एक दो ट्यूबवैल लगाने की कृपा की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसको एग्जामिन करवा लेंगे और अगर लगने की सम्भावना होगी तो लगवा देंगे।

Transfer to Teachers

***1022. Chaudhri Ram Kishan:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that teachers belonging to Safidon Constituency have been posted in the Schools of District Kurukshetra;

(b) whether it is also a fact that Teachers belonging to Sonapat District have been posted in Safidon Constituency; and

(c) if so, whether Government intends to transfer the said teachers to their home District, if not, the reasons therefore?

शिक्षा मंत्री(श्री हीरानंद आर्य): अध्यक्ष महोदय, श्री रामकिशन जी का जो सवाल है वह पिछले दिनों जो जे०बी०टी० टीचर्स की सिलेक्शन हुई है उससे संबंधित है। उस सिलेक्शन में जींद जिले के लिये 236 स्थानों के लिये नाम रिक्त किये

गये थे लेकिन रिक्त स्थान नहीं थे जिसके कारण 189 नाम कुरुक्षेत्र के लिये रिक्त किये गये थे तो इसलिये सोनीपत के आदमियों को सफ़ीदों में भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपस में मिल कर म्यूचल ट्रांसफर की कोई बात होगी तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

चौधरी राम किान: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में केवल यह कह कर टाल दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उनके इस जवाब को चैलेन्ज करता हूँ कि मेरी कास्टीच्युएन्सी के अन्दर अब भी सोनीपत के 30-35 जे0बी0टी0 और बी0एड0 टीचर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने जवाब में कह दिया है कि कोई नहीं है। यह गलत कह कर यूँ ही हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना थी, वह मैंने इस हाउस के सामने रख दी है। अगर आनरेबल मैम्बर के पास कोई ऐसी रिपोर्ट हो तो वह मुझे लिखकर भिजवा दें, मैं इन्क्वायरी करवा लूँगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आनरेबल मैम्बर को सुजैस्ट करूँगा कि ऐसा कोई नाम उनके पास हो तो वह लिखकर आनरेबल मिनिस्टर साहब के पास भिजवा दें, और मुझे पक्की उम्मीद है कि आनरेबल मिनिस्टर उस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या कल इस सवाल पर सप्लीमेंटरी हो जाएगी।

Mr. Speaker: कल के लिये, there is no rule to carry over the supplementaries. इस सवाल का जवाब आ चुका है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Grades of D.S.Ps.

***1052. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to bring the grades of D.S.Ps. at par with H.C.S. Officers?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेंद्र सिंह): उप पुलिस अधिकाओं के वेतनमान सं गोदित करने के लिये प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और निर्णय लिया गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाएं।

Subsidy to Farmers

***1052. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant subsidy to the Farmers who get their water courses lined; if so, the amount of subsidy proposed to be given to them?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेंद्र सिंह): मोगे के चक के सारे भागीदारों को खालों के पक्का करने के खर्च पर सहायता करने की कोई प्रयोजना नहीं है किन्तु लघु तथा सीमांतक किसानों को एस0एफ0डी0ए0 तथा एम0एफ0 वाले खंडों में तथा इनके इलावा उन खंडों में जहां एस0एफ0डी0ए0 आदि का प्रोग्राम अभी तक लागू नहीं, वहां हायता की प्रयोजना है।

भारत सरकार की एस0एफ0डी0ए0 तथा एम0एफ0ए0एल0 के बिना खंडों में लघु तथा सीमांतक किसानों से वसूली होने वाले खर्च का 50 प्रति शत सहायता देने की प्रयोजना है।

जूई उठान सिंचाई योजना के क्षेत्र में एस0एफ0डी0ए0 तथा एम0एफ0ए0एल0 से मिलने वाली मदद के अलावा सी0ए0डी0ए0 ने 10 खालों पर सारे भागीदारों को विशेष रूप से सहायता दी है। भविश्य में यह सहायता केवल लघु तथा सीमांतक किसानों तक ही सीमित रखी जायेगी।

अंतरांकित प्रश्न एवं उत्तर

Country liquor and Indian made Foreign liquor Shops

240. Swami Adityavesh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the total number of vends of country liquor and Indian made foreign liquor shops at present in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to close the Indian made foreign liquor shops in the State; and

(c) if so, the details thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह):

(ए) (I)	देसी भाराब की दुकानें	312-13 थोक की दुकानों सहित
(II)	भारत में बनी विदे गी भाराब (आई०एम०एफ०एल०) की दुकाने	497-45 थोक की दुकानों सहित

(बी तथा सी) वर्ष 1979-80 में बनी विदे गी भाराब की 40 प्रति शत दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

Allotment of Nazool Land

241. Swami Adityavesh: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the lease holders of the Nazool land only are entitled to its allotment or it can be allotted to other persons also; and

(b) whether the Nazool land is auctioned by the Government in open auction?

राजस्व मंत्री(श्री प्रीत सिंह):

(ए) नजूल भूमियां दो प्रकार की होती हैं। एक नजूल भूमि (एसचीटिड) तथा दूसरी भूमि (नान-एसचीटिड)। नजूल भूमि (एसचीटिड) नजूल लैंड (हसतांतरण) नियम, 1956 के अधीन केवल अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को अलाट की जाती है। अलाटमेंट के संबंध में इन जातियों के पट्टेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। रिहाय गी प्लाट खुली बोली द्वारा बेचे जाते हैं।

(बी) जैसा कि ऊपर (ए) के अधीन बताया जा चुका है कि नजूल भूमि (एसचीटिड) का नीलामी द्वारा निपटान नहीं किया जाता है। नजूल भूमि (नान-एसचीटिड) का निपटान खुली बोली द्वारा अथवा आपसी बातचीत द्वारा किया जाता है। इन भूमियों का निपटान उप मंडल स्तर पर सरकार द्वारा गठित नजूल भूमि (नान-एसचीटिड) निपटान इन कमेटियों की सिफारिश अनुसार किया जाता है।

**Comensation for the construction of Mirks
Minor**

242. Swami Adityavesh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the compensation has so far been paid to the farmers in respect of Mirka Minor constructed during the year 1961, in Nuh Tehsil of District Gurgaon; and

(b) if reply to part (a) above be in the negative, the reason therefor and the time by which the compensation is likely to be paid?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेंद्र सिंह):

(अ) मिर्का माईनर से संबंधित भूमि के मुआवजा की अदायगी की स्थिति निम्नलिखित है:-

कुल मुआवजा अदायगी करने वाली रकम 11615-97 रूपये थी जिसमें से जमींदारों को रूपये 8829-91 को अदायगी 25-1-1962 तथा 1-3-1962 को की गई थी बकाया रूपये 2786-06 की रकम भूमि अधिग्रहण अधिकारी अम्बाला के हवाले कर दी गई थी ताकि जो भी जमींदार मुआवजा लेने आवे तो उन्हें अदायगी कर दी जाये। इस बकाया रूपये 2786-06 में से भूमि अधिग्रहण अधिकारी अम्बाला ने रूपये 2400-11 की रकम जमींदारों को अदा कर दी है। अब केवल रूपये 385-95 की राशि बकाया है जोकि जमींदारों को देनी है। जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी रोहतक ने सूचित किया है कि अभी तक जमींदार उपर्युक्त बकाया रकम को लेने नहीं आए है। यह बकाया रकम भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने पलवल खजाना में जमा करवा रखी है और अभी तक वही जमा पड़ी है।

(अ) केवल रूपये 385-95 नाम मात्र रकम है जोकि जमींदारों को जब भी वे आएंगे उन्हें अदा कर दी जाएगी।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

1. उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सम्बन्धी:-

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, मैंने कंज्यूमर्ज गुड्ज की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बारे में एक काल अटेन न मो न दिया था

15.00 बजे

Mr. Speaker: Hon. Member, I have received a notice of a Call Attention Motion from Sh. Shamsheer Singh Surjewala, M.L.A. concerning the rise in prices of certain consumer goods after the presentation of the Central Budget. I have disallowed it on two counts. Firstly, this is a subject matter for the Central Government and, as such, the Lok Sabha is the proper forum for this subject and not the Haryana Vidhan Sabha. Secondly, vide Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shukdher page 618, the provision of the Finance Bill relating to the imposition or increase in duties of custom or excise come into force immediately on the expiry of the day on which the Bill is introduced.

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बजट के खिलाफ कोई एतराज नहीं किया था कंज्यूमर गुड्ज पर जो बजट के बाद कीमतें बढ़ी हैं उन कीमतों को मेनटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सैन्ट्रल बजट के कुछ आधारों की वजह से प्राईसिज बढ़ी है जो आपने लिखा है। They come into force with immediate effect.

(ii) हरियाणा डाकखानों में बेनामी जमा राशियों सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of Call Attention Motion from Swami Aditya Vesh, M.L.A. concerning the deposits in benamis in Post offices in Haryana. I have disallowed the same as it concerns the department of Posts and Telegraph which is a Central Government subject and as such cannot be discussed in the Haryana Vidhan Sabha. Further, a question on this subject had been discussed in the Lok Sabha and, therefore, undoubtedly the Central Government must be seized of the problem.

(iii) टपरीवासियों तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: मुझे सर्वश्री अग्निवे 1, आदित्यवे 1, भांकर लाल, गया लाल जगन नाथ, सुमेरचन्द भट्ट तथा श्रीमति सुशमा स्वराज, एम.एल.एज. की तरफ से टपरीवास तथा विमुक्त जाति को रिजर्व्ड कास्ट की लिस्ट में से निकाल कर रिजर्व्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में शामिल करने और उनको कुछ सहूलियतें देने के बारे में एक ध्यान दिलाओं प्रस्ताव का नोटिस मिला है और मैं उसको मन्जूर करता हूँ। स्वामी अग्निवे 1 जी अपने प्रस्ताव को

पढ़ दें और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी मंत्री जी अब अपना ब्यान दे सकते हैं या कुछ समय मांग सकते हैं।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के इस आव यक मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह हम सबके लिए बहुत खेद की बात है कि विमुक्त जाति, टपरीवास जैसे पिछड़े वर्ग सदियों से पिछड़े हुए चले आ रहे हैं। इन विमुक्त जातियों का प्रस्ताव नं. 22 सन् 1793 और 1871 के अनुसार विभिन्न कबीलों का नाम देकर जुरायन पे गा जैसा कठोर कानून लगा दिया गया था और इन जातियों को अपनाधी कबीले, नोमेडिक ट्राईब, बाजीगर, ट्राईब इत्यादि के नाम से पुकारा गया और इसी प्रकार इन कगीलों का नाम 31 अगस्त 1952 तक रहा और 31 अगस्त , 1952 तक जुरायन पे गा जैसा कठोर कानून भी लागू रहा।

हरियाणा राजय में विमुक्त जाति टपरीवास जैसे इतने बड़े वर्ग सिमें 32 जातियां आती है जैसे सहांसी,, बाजीगर, सीकलीगर, कुचबन्दे, नट, डेह भेडकुट, सपेले, बोरिये और सिंगीकार इत्यादि का एक भी एम0एल0ए0 एम0पी0 , आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 तथा एच0सी0एस0 अधिकारी नहीं है।

31 अगस्त 1952 से पहले इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा हुआ था। परन्तु उसके बाद इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रख दिया गया। जिसका लाभ कुछ एक विशेष जातियाही उठा रही है। और इन विमुक्त जातियों को हर क्षेत्र में हानि उठानी पड रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 339(2), 15(4), 16(4) और 46 के अनुसार राज्य सरकारो का विमुक्त जाति जैसे पिछडे वर्ग को विशेष सुवधायें देने का अधिकार है। उपरलिखित संविधानिक धाराओं ओर जनता पार्टी के चुनाव घोशणा-पत्र और भारत के प्रधान मंत्री व गृह मंत्री के चुनाव घोशणा के अनुसार विमुक्त जातियो जैसे पिछडे वर्ग को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। अतः हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित मांगो को अविलम्ब पूर्ण करने की कृपा करे।

(1) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि टपरीवास तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में से निकाल कर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये।

(2) इन जातियों का एक अलग निदेशालय खोला जाए।

पकड़ लेंगे दूध कभी पकड़ा नहीं जाता और बाद में गाय भी गई और बछड़ा भी गया। चौधरी देवी लाल जी ने 40

केलोमीटर का रकबा दिल्ली के आस-पास निर्धारित कर दिया और अच्छे किस्म के बीज, सबसिडी सब्जियों के लिये , मुर्गीपालन के लिये और डेरी डिवैल्पमेंट के लिये सरकार जो हैल्प देगी उससे दूध अधिक उत्पन्न होगा। यह चीज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस देश में जो सबसे अच्छा काम हुआ है वह है खेलकूद के मैदान में प्राथमिकता लेना। खेलकूद के मैदान में हरियाणा इस देश में अग्रणी रहा है और जब देश में एग्रीकल्चरल टूर्नामेंट में हरियाणा प्रथम रहा तो उनको प्राइज देने के लिये 57 हजार रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई और हर ब्लॉक में दो खेलकूद के सैंटर खोलने का फैसला किया गया है ताकि हरियाणा के बच्चों का भविष्य निःसन्देह सराहनीय बन सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कम्पलसरी इन्फोर्सेंस की जाये। किसान की फसल खलियान में पड़ी रहती है उसकी कम्पलसरी इन्फोर्सेंस कर दी जाये। सोहना में इस साल बड़ी अच्छी फसल थी लेकिन बाई चांस कल भाम को इतना ओला पडा कि 80 प्रतिशत फसल का लौस किसान को हो गया। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि किसान को राहत पहुंचाने के लिये सरकार पूरा जोर लगा दे और इसके साथ ही साथ किसान की फसल की कम्पलसरी इन्फोर्सेंस भी जरूर कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि सरकार की 195 करोड़ रूपया ग्रामीण विकास पर खर्च कयरने की योजना हैं इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हर एक गांव में लैटरिन की बड़ी दिक्कत आती है खासतौर पर बरसात के दिनों में भाँचालय की बड़ी दिक्कत होती है और विशेषतौर पर बहनोंको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पडता हैं आज के युग में जहां हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, गोबर गैस प्लांट के लिये कर्जा दे रहे हैं सबसिडी दे रहे हैं इसी प्रकार बनवाने के लिये एक विशेष राशि निर्धारित की जानी चाहिये और हर ब्लॉक को आदेश जारी किये जायें कि ज्यादा रूपया लैटरिन बनाने पर खर्च किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिये सरकार ने वचन दिया है कि पांच साल के अन्दर हरियाणा में जितने गांव हैं, उन सब को पीने का पानी दिया जाएगा। यह बक बहुत बड़ा काम होगा। अध्यक्ष महोदय, बुद्धिजीवी वर्ग, जो फिफथ एस्टेट कहलाता है, इस वर्ग से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं और जो नई योजनाये हैं उनको प्रैस मेंविस्तारपूर्वक दिया जाये ताकि गरीब जनता उसका पूरा फायदा उठा सके। ये लोग जो बुद्धिजीवी हैं, भारत के बदलते हुये नक्शे को बनाने में अपना हाथ बटायें। जनता सरकार की जो उपलब्धियों हैं, जैसे सरकार ने कोटा परमिट को समाप्त किया। कोटा परमिट के तहत पहले हम एक जगह से दूसरी जगह चावल नहीं ले जा सकते थे, गेहूँ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन आज कोटा परमिट खत्म करने से आप ट्रक भर कर जहाँ मर्जी चाहें, कोचीन तक ले जा सकते कोई

रोकने वाला नहीं है। सरकार ने कोटा परमिट खत्म किया, सवा छः एकड़ तक जमीन पर मालिया खत्म किया। गांव में जाकर आप देखे। कितने छोटे-छोटे जमींदार हैं और अगर उनसे जाकर पूछें तो कि कितने छोटे जमींदार हैं तो 80 परसेंट लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। इन 80 परसेंट लोगों के लिये सवा छः एकड़ पर मालिया माफ, टोकन टेक्स जो ट्रैक्टर पर लगता था वह माफ कर दिया गया है और खाद की कीमत कम, तेल की कीमतें कम कर दी गयी हैं। हम पहले 12-13 रुपये किलो तेल खरीदा करते थे, अब 9 रुपये किलो मिल रहा है.....

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड-अप करें।

कंवर विजय पाल सिंह: अभी खत्म कर रहा हूँ जी। इसी प्रकार से जबरदस्ती नसबन्दी करना भी बन्द कर दिया गया है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के मुताबिक नसबन्दी स्वेच्छा से की जाएगी, फैमिली प्लानिंग स्वेच्छा से की जाएगी। इसी तकरह बिजली पर फ्लैट रेट लागू करना सटूडेंट्स के लिये बसों में चलने की अधिक सुविधा प्रदान करने का काम और इसी प्रकार के कई अन्य सराहनीय काम इस जनता सरकार ने किये हैं।

श्री भाम ेर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज तीसरा और अन्तिम दिन है। अभिभाषण के पैरा न0 4 में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा आर्थिक व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करने के लिये अधिक बिजली

पैदा करना, देहातों में सड़को का निर्माण करना और यातायात के साधनों को सुदृढ़ करने का खास तौर पर जिक्र किया गया है। स्पीकर साहब, पैरा न0 4 में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की जा`बात कही गई है उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा इस सदन को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जनाता पार्टी की सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या बनायेगी, यह तो पहले ही बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज से सात आठ साल पहले, जब हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल थे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का राज था, उसने न सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर ले किया था ? बल्कि इकोनामी को भी टेक-आफ कर यिलाथा, लेकिन आज जनता सरकारने उसको कै । लैण्ड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकडे देकर यह बात साबित करता हूं। इस अभिभाषण में दिये गये आंकडे इल्लयूजनरी है, भ्रामक है। दरअसल हरियाणा की पोजी इन कांग्रेस राज में क्या थी, यह आपके सामने आंकडे देकर रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1071 की सैसिंज के मुताबिक हरियाणा में 6731 गांव थे । 1971 में कांग्रेस सरकार ने सैन्ट परसैंट गांवों को बिजली दी, सारे गांवों को इलैक्ट्रिफाई किया। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये) इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 1971, में टोटल इलैट्रिसिटी लोड एग्रीकल्चर सेक्टर में 45 परसैंट था जो सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा था, इस क्षेत्र में हरियाणा पहले नम्बर पर आता था। इसके बाद मैं सड़को की बात करूं तो डिप्टी स्पीकर साहब, 1975 तक 73 परसैंट गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया था, इसके मुकाबले में जब 1 नवम्बर, 1966 में

हरियाणा बना था, उस वक्त केवल 5100 किलोमीटर पक्की सड़के थी और 1386 गावों की सड़कों से जोड़ा गया था जो कुल गांवों का 20 परसेंट बनता है। कांग्रेस सरकार ने 31 मार्च, 1979 तक 9800 किलोमीटर सड़के हरियाणा में बनाई और 4890 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया जो कुल गांवों का 73 परसेंट बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं हरियाणा में बस-सर्विस का जिक्र भी करना चाहता हूं। मार्च, 1975 में बसों की तादाद 2000 थी और हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की बस सेवा सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में पहले नम्बर पर थी, सबसे ज्यादा कामयाब थी, हरियाणा की इस बात का श्रेय दिया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता देता हूं कि जिस वक्त हरियाणा बना था, उस वक्त पर-कैपिटा इन्कम के लिहाज से हरियाणा हिन्दुस्तान में 11 वा नम्बर की स्टेट थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने राज छोड़ा उस वक्त हरियाणा का नम्बर, पर-कैपिटा इन्कम के लिहाज से दूसरे नम्बर पर था और आज भी हरियाणा दूसरे नम्बर की स्टेट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सारे हरियाणा के लोग बसों या रेलों में सफर करते हुए या गांव में हुक्के के ऊपर जो बात कहते हैं वही मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। लोग आज कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने जो सड़के बनाई थी जनता पार्टी की सरकार उगर उनको ठेगली भी लगा दे तो इसकी मेहरबानी है। इसी तरह से वह कहे हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा बिछाई गई बिजली की तारों में से टूटी हुई तारों

को भी यदि जनता पार्टी की सरकार जोड़ दे तो इनकी मेहरबानी है। यही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए हस्पताल आदि के भवनों, रैस्ट हाउसिज और टूरिज्म वगैरा के भवनों में अगर यह सरकार सफेदी भी करवा दे तो इनकी बहुत मेहरबानी है।

स्वामी अग्निवे : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। यह जो अभी कहा जा रहा है कि जनता ऐसा कहती है या वैसा कहती है यह गलत बात है। जनता तो यह कहती है कि बंसी लाल ने जो कुछ किया है उसके लिये यदि देवी लाल जी उनको जेल में ठोक दे बड़ी मेहरबानी होगी। (गोर)

श्री भाम गोर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी की कौनसी बात पर यकीन किया जाए। कांग्रेस राज में तो स्वामी जी चौधरी बंसी लाल जी को कृष्ण का अवतार बताते थे और बीस सूत्री कार्यक्रम को गीता का उपदे ग बताते थे लेकिन आज चौधरी देवी लाल जी को खु ग करने के लिये ये ऐसी बातें करते हैं पता नहीं इनकी कौनसी बात ठीक है?

स्वामी अग्निवे : यह बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको प्रिवलेज कमेटी में ल जाऊंगा। मैंने कभी यदि इस प्रकार की बात कही हो तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और यदि इनकी बात गलत हो तो इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (विधन एवं भाोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: मैं इस बात का गवा हूँ। जिस मीटिंग में आपने यह कहा था वहा मैं भी था।

श्री भाम ार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर के इस अभिभाषण में अनाज की पैदावार का हरियाणा के गांव का और किसान का बहुत बढ़ चढ़ कर जिक्र किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि किसान की हालत अच्छी न हो, गांव की हालत अच्छी न हो लेकिन असलियत जो है वह इसके उलट हैं उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के द्वारा मैं यह बात सिद्ध कर सकता हूँ। 1966-67 में हरियाणा में अनाज को पैदावार 25 लाख टन थी लेकिन कांग्रेस राज आने के बाद 1970-71 में यह बढ़ कर 48 लाख टन हो गई और जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी 1976-77 में उस वक्त यहां अनाज की पैदावार 52 लाख 50 हजार टन हो गई थी। हरियाणा सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इस पैम्फलेट के अनुसार 1977-78 में यह पैदावार 53 लाख 61 हजार टन बताई है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग एक लाख टन अनाज की पैदावार बढ़ी है उपाध्यक्ष महोदय, पैदावार की इस बढ़ौतरी की औसत पर अगर हम नजर डाले तो पिछले दस साल में यह सबसे कम पैदावार बनती है उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ अनाज की अधिक पैदावार का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो अन्न पैदा करते हैं उनको इसकी तिनी कीमत मिलती है। कांग्रेस राज में आप जानते हैं गन्ने को 14 रूपये से

लेकर 16 रूपये क्विटल तक मिल खरीदती थी और क्रै र्ज आठ रूपये में दस रूपये क्विटल तक खरीदते थे। इसी तरह से गुड़ की कीमत 250 रूपये क्विटल, सरसों की कीमत 450 रूपये क्विटल, बाजरे की कीमत 125 रूपये क्विटल, कोटन 500 रूपये क्विटल और आलू का भाव 60 रूपये प्रति बैग था। लेकिन आज जनता पार्टी के राज में क्या हुआ? इसमें कोई भाक नहीं कि हरियाणा सरकार ने मिलों के लिये गन्ने का भाव साढ़े बारह रूपये क्विटल मुकर्रर किया है लेकिन मिलों का एरिया 10 परसैन्ट से ज्यादा नहीं है। 80 परसैन्ट एरिया में तो क्रै र्ज है। उनके बारे में अभी मेरी बहिन भान्ति राठी जी ने बताया कि उस एरिया में तो दो या तीन रूपये से ज्यादा कीमत किसान को नहीं मिलती। मिलों की हालत भी आप देख लीजिए। 20 फरवरी तक यमुनानगर की सरस्वती मिल ने नौ रूपये और दस रूपये प्रति क्विटल के हिसाब से गन्ना खरीदा है, बारह रूपये और साढ़े बारह रूपये क्विटल के हिसाब से उसने गन्ना नहीं खरीदा उसके बाद भी और आज भी जमनानगर मिल दस रूपये से ज्यादा भाव किसान को नहीं दे रही है इसकी वजह से आज सारे हरियाणा में गन्ना पैदा करने वाले किसान की हालत बड़ी खराब है दूसरी चीजों को भी यही हाल है आज गुड़ का भाव 60 रूपये और 70 रूपये क्विटल है बाजरा 60 रूपये क्विटल से फालतू नहीं है अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल हरियाणा की नहीं बल्कि सारे हिन्दूस्तान की बात करता हूँ क्योंकि हरियाणा अलाहिदा आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में 70 लाख गांठ कपास की पैदा होती है। एक गांठ में

170 किलों कपास होती है। कपास का पहले 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव था लेकिन आज भाव 250 रुपये क्विंटल हैं लगभग 250 रुपये क्विंटल का फर्क है। अगर हम किसान को मिली इस घट कीमत का हिसाब लगाएं तो 3 अरब 97 करोड़ रुपये का लौस हिन्दुस्तान के किसान को जनता पार्टी की सरकार के राज में हुआ है, जिसमें हरियाणा पंजाब और यू०पी० का ज्यादातर एरिया शामिल है। इतना घाट अकेली कपास में हुआ है इसी तरह अरबों का नुकसान गुड और गन्ने में हरियाणा और पंजाब के किसानों को हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, मैं गन्दम और जीरी की भी बत करना चाहता हूँ डेढ़-दो साल पहले गन्दम का भाव 112 रुपये 50 पैसे क्विंटल मुकर्रर किया गया लेकिन रिकार्ड की बात है कि 108 रुपये क्विंटल से ज्यादा गन्दम का भाव किसान को नहीं मिला। मेरे पास अखबारों की कटिंग है। जिनके मुताबिक हरियाणा की गन्दम पंजाब की मंडियों में बिकती रही क्योंकि वहां 112 रुपये 50 पैसे क्विंटल का भाव किसान को मिलता था। जीरी का भाव 85 रुपये क्विंटल सरकार ने मुकर्रर किया था लेकिन 70 रुपये क्विंटल से फालतू का भाव हरियाणा के किसान को नहीं मिला। दो दो हफ्तों तक लोग जीरी लेकर मंडियों में पड़े रहते थे। इसमें पिलफ्रेज जो हुई उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यही बस नहीं पिछले नवम्बर-दिसम्बर में जब गन्दम की बिजाई का वक्त था तो हरियाणा के किसान को 1 रुपये 40 पैसे लीटर वाला डीजल दो रुपये से लेकर दो रुपये पच्चास पैसे प्रति लीटर ब्लैक में खरीदना पड़ा। यह भी तब जब 15 दिन

तक उसका ट्रैक्टर और आदमी पेट्रोल पम्प पर बैठा रहा। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें होने के बावजूद भी यह सरकार हरियाणा के किसान का हमदर्द होने का दावा करती है जबकि सचार्ई यह है कि इस सरकार के राज में बहुत माली नुकसान किसान को हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं रूरल इंडस्ट्रिययलाइजे ान के बारे में, जिसकी बड़ी भारी चर्चा है, कहना चाहता हूं। ये कितने झूठे आंकड़े है और कितनी बोगस बात है। उपाध्यक्षा महोदय, इसी ऐड्रैस में आंकड़े दिये गये हैं इस चालू साल में 330 यूनिट्स खोलने का सरकार का लक्ष्य है। एक यूनिट को चार आदमी इकट्ठे मिल कर चालू कर सकते है। इस तरह कुल 1320 आदमियों को रोजगार मिल सकता है। अगले पांच सालों में 1900 ऐसी यूनिट्स खोलने का सरकार का विचार है। 1900 यूनिट्स अगर सरकार लगाती है तो केवल साढ़े सात हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है लेकिन जो सरकार ने आंकड़े दिये है उनके अनुसार डेढ़ लाख बेरोजगार मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलते हुए 33 मिनट हो गये है इसलिए आप वाइंड-अप करे।

श्री भाम ोर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अीी तो मुझे तीन मिनट भी नही हुए है मुझे वाइंड-अप करने के लिये भी तो टाईम चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय मैं आप के जरिए हाउस क नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा में सन् 1978 में मैन डेज लोस्ट की

तादाद 470189 है जो स्ट्राईक की वजह से हुई है और लोक आउट के कारण 1,13,534 मैन डेज लोस्ट हुए हैं। हरियाणा इन आंकड़ों के हिसाब से हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है। हरियाणा के अन्दर लेवरर्ज में भी बड़ा अन-रैस्ट रहा है। डालमिया दादरी फ़ैक्टरी, हिसार टैक्सटाइल मिलज, जिन्दल पाईप फ़ैक्टरी हिसार, एटलस फ़ैक्टरी सोनीपत, एच०एम०टी० मैटल वर्क्स जगाधरी के मजदूरों में बड़ा भारी अन-रैस्ट रहा है इसी तरह से फरीदाबाद में भी मजदूरों ने हड़ताल की है उन लोगों की नौकरिया छीनी गई, हरियाणा सरकार ने मिल मालिकों से मिल कर पुलिस से रिप्रेान करवाया, कई जगहों पर गोलिया चलाई गई, मजदूरों पर झुठे मुकदमें बनाये गये। इस सरकार के आने के बाद मजदूरों में आंतक फैला हुआ है और सारे हरियाणा में त दूद का वातावरण बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिए हाउस को यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के गवर्नमेंट मुलाजमों की आज क्या हालत है? पिछले दिनों स्कूल टीचर्ज, कालेज टीचर्ज हैल्थ वरकर्ज, तीसरी और चौथी श्रेणी के छोटे कर्मचारी, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, लैन्ड मार्गेज बैंक और एग्री इन्डस्ट्रीज के कर्मचारी हड़ताल और धरने पर बैठे हुए थे। यह डेढ़ साल से स्थिति चली आ रही है। इसी तरह से हरियाणा मिलक प्लांट एम्पलाईज असोसिएान के कर्मचारी भी पिछले डेढ़ साल से हड़ताल और धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। उनकी

मांग है कि इस पे-कमी इन को स्क्रेप किया जाये और जो पंजाब पे-कमी इन की रिपोर्ट अभी आने वाली है उसी की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा गवर्नमेंट मुलाजिमों को भी रिलीफ दिया जाये क्योंकि अब जो पे-कमी इन बैठा है यह तो कम से कम दो साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस लिये वहां पर बहुत पहले से कमी इन बैठा हुआ है उसी के आधार पर हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय इस ऐड्रेस के पैरा 37 में जन-वितरण प्रणाली का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुज्युमर स्टोर्ज के द्वारा कपड़ा और दूसरी जरूरियाते-जिन्दगी की चीजें दी जायेंगी। जैसे मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि चीजें दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता है तमाम हरियाणा में किसी भी गांव में कोआपरेटिव सोसाइटीज से कोई चीज नहीं मिलती है जो भी कन्ज्यूमर गुड्स सप्लाई करते हैं उसकी कीमत मनमाने ढंग से चार्ज की जाती है।

हरियाणा में सरकारी खर्च में भी कमी करने की बात कही गई है इस बारे में तो कहूंगा कि यह सबसे बड़ा मजाक है क्योंकि हमारे उद्योग मी जी का टेलीफोन का ही खर्च 1 लाख 93 हजार रुपये 17 महीने का है और एक लाख पचास हजार रुपये पेट्रोल का खर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष: इस बारे में हाउस में जवाब आपके सवालसे आ चुका है इसको आप रिपीट न करे।

श्री भाम ार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मकसद यह है कि हरियाणा सरकार का मन्ा अपने खर्चे में कमी करने का नहीं है। मन्त्रियों को तो और भी बुरा हाल है, उनके बराबर तो कोई नमूना पेा नहीं कर सका।

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भाम ार सिंह जी ने एक लाख 93 हजार रूपया जो बताया है, यह गलत बताया है क्योंकि चौधरी देवी लाल जी ने ठीक ही कहा है कि इनको गलीत बोलने और * * * * बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है। (विधन)

श्री भाम ार सिंह: यह * * * * अन-पालियामेंटरी भाब्द है, इसको एक्सपंज कराना चाहिए। (ार)

चौधरी राजेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने बोलना है इसलिए टाईम का ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखा जाये।

श्री भाम ार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि डा० मंगल सैन जी 352 दिन टूर पर रहे हैं (ार)

डा० मंगल सैन: जनता की सेवा के लिए जितना भी हम टाईम लगा सकते हैं, जरूर लगायेंगे और इसी सेवा के लिये हम चुन कर आये हैं। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग क्या हाउस का समय जाया कर रहे हैं। आप भान्त रहे।

डा० मंगल सैन: जनता की सेवा न करने के कारण ही तीन चुन कर आये ही (विघ्न)

श्री भाम गोर सिंह: डाक्टर साहब आपके लिये तो हम तीन ही काफी हैं। (विघ्न)

डाक्टर मंगल सैन: आप तो तीस भी आ जाते तो भी काफी नहीं होते। आप तो पुरानी बातों को याद करके रो रहे हो।

श्री भाम गोर सिंह: डाक्टर मंगल सैन जी ने तीन बात की है। * * * * को पकड़ने के लिये तो एक ही चौकीदार काफी है।

डाक्टर मंगल सैन: * * * * ये होंगे। इसी लिये तो इनको हथकड़ियाँ लग रही हैं। आपने नेता जो प्राईममिनिस्टर बनना चाहते थे उनको ही पकड़ा जा रहा है। वहाँ सैंटर में संजय गांधी था और यहाँ पर सुरेन्द्र अपने बराबर किसी को भी नहीं समझता था। इनको * * * * आनी चाहिए। * *

* * दो दो साल की सजा हो रही है। (विघ्न) आप

लोगों के खिलाफ ही कमी उन बैठे हुए है। (विधन) आप लोगों के खिलाफ ही कमी उन बैठे हुए है। (विधन)

चौधरी लाल सिंह (सढ़ोरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि इतने बड़े संघर्ष के बाद आपने मुझे टाईम दिया है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सम्मुख पेश किया है मैं उसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस राम राज की सदियों से तलाश थी वह आज हरियाणा में आ गया है जो आदमी अपने हकों के लिये सदियों से लड़ रहे थे आज उनको वह हक प्राप्त हो गया है उस टाईम पर किसी भी व्यक्ति की बोलने की हिम्मत नहीं थी कि किसी के बारे में कोई बात कहे दे लेकिन आज हम सदन में और बाहर भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन ये लोग फिर भूल जाते हैं और हमारे मिनिस्टर्स का आज पहले के मिनिस्टर्स से मुकाबला करते हैं। 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'। मेरे जैसे आदमी को 19-19 महीने तक अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। कम्बल भी फटे हुए दिये गये। सरदार लछमन सिंह जी जैसे भारीफ आदमी को लड़की की भाादी में नहीं आने दिया गया। अब किसी कातिल की लड़की की भी भाादी होती है तो उसे भी भाादी में जाने देते हैं। चौधरी देवी लाल जैसे देवता आदमी को कच्ची रोटियां खाने को दी गयी और सूजी हुई टांगे होने के बावजूद डाक्टर को अटैन्ड नहीं करने दिया गया। आज वे अपने जुल्म भूल

गये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस राम राज्य वाली सरकार ने आते ही क्या किया। इसके आते ही पहले तो दो फ्लड आ गये। एक फ्लड तो ऐसा आ गया था कि उससे सारा हरियाणा ही पानी में डूब गया था। उसके बाद हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल, डाक्टर मंगल सैन जी और दूसरे हमारे सारे नेता गांव-गांव में गये और लोगों की जाने बचायी। हमारे अफसर जिन्हें पिछली सरकार ने खराब बना दिया था उन्होंने इतने-इतने पानी में जाकर लोगों की मदद की। लोगों को दुबारा जन्म मिला। यह सब को पता है कि हमारे यहां फ्लड आया। इसके बाद दूसरा फ्लड आया जिसके बारे में सिर्फ उन भाईयों को पता है जो इसे लाये यह फ्लड आया जिसके बारे में सिर्फ उन भाईयों को पता है जो इसे लाये थे। ये कांग्रेसियों का काम था जो इस सरकार को खत्म करकने के लिये वह फ्लड लाये थे चौधरी देवी लाल ने इस फ्लड को जो पोलिटीकल हमले का था, रोका और उसमें भी कामयाब हुए। तो इस तरह से दो तो असली फ्लड आये थे और तीसरा पोलिटीकल हमले का फ्लड आया था जिन्हे यह सरकार रोकने में कामयाब रही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल की सरकार को अनस्टेबल बनाने वाले डाक्टर मंगल सैन जी है और कोई नहीं।
(विघ्न)

डाक्टर मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी अभी तो मेरे भाई मुझे लौबी में कुछ और ही कर रहे थे। यह अब यहां पर आते ही बदल गये है।.....

चौधरी जगजी सिंह पोहलू: आपने इस्तीफा नहीं दिया था?

डाक्टर मंगल सैन: पोहलू साहब, मेरे से सारी बातें—क्यों कहलवाते हो? यह कोई एक् इन नहीं लेगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इस संबंध में मैंने गवर्नर साहब को भी लिख कर भेज रखा है और मुख्य मंत्री जी को भी और होम मिनिस्टर को भी लेकिन उस पर कोई एक् इन नहीं हुआ। जहां तक एम०एल०एज० की बात करते हैं, यहां हमारे आदरणीय साथी कहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष: मांगे राम जी, बोलने वाले काफी मैम्बर साहेबान हैं और समय कम है इसलिए आप पांच मिनट तक बोल लें।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में हमारा टाईम फिक्स हो चुका है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, आप इनके लिये समय और क्यों नहीं बढ़ा लेते, क्योंकि अगर किसी मैम्बर को बोलने के लिये टाईम नहीं दिया जाएगा तो वहां अपनी बात कैसे कहेगा?

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, इतने समय में तो मैंने अपनी कई बातें कह लेनी थी। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस राज में एम०एल०ए० की पोजी इन क्या है? मैंने 15-1-79 को डी०सी० जी०द को लिख कर दिया कि इस आदमी ने पचास लाख का घोटाला किया है। मैंने कहा कि आप एक हफ्ते के अन्दर अन्दर इस बात का जवाब दें कि क्या यही एक आदमी है जिसने सात जगहों पर कब्जा करके 50 लाख रुपये हजम करने चाहे है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, आज तक डी०सी० ने 15-1-79 से लेकर 6-3-79 तक का समय दो महीने से ज्यादा निकाल दिये है लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास जो प्वायंट्स है वे भी मैंने रिटन में मुख्य मंत्री को भेजे है और उनक `बारें में भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वह प्वायंट्स मैं यहां सदन की पटल पर रख देता हूं और अगर आप कह तो मैं आपको दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझे दे दें, मैं एग्जामिन करवा लूंगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहब, इस आदमी ने पेट्रोल पम्प ले रखा है और गलत जगह पर कब्जा करके लगाया सो लगाया लेकिन पिछले दिनों जब पेट्रोल की दिक्कत थी, डीजल की दिक्कत थी और किसानों को चार चार दिन तक डीजल नहीं मिल रहा था तो उस आदमी ने सारे का सारा डीजल ब्लैक में बेचा। जब लोगों ने इस बात की रिक्वायत डी०सी० के पास की तो उसने भी इस चीज को रोकने के लिये कोई कदम नहीं

उठाया। वह आदमी यह जवाब देता था कि जो मैंने पेट्रोल पम्प लगाया है वह लाईन में लगकर पेट्रोल देने के लिए नहीं लगाया है। जो कुछ आपने करना है वह कर लो। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी यह नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे दूसरी तरफ इस संबंध में एक एम०एल०ए० लिख कर देता है तो हमें सूचना तक नहीं मिलती, यह भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं नहीं समझ सकता कि यह सरकार इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार खत्म कर सकती है डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे में जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तब हमने लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करके उसका खिलाफ आवाज पैदा की। डिप्टी स्पीकर साहब, उसका नतीजा यह हुआ कि अकेले मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे भाई पर, मेरे भाई के लड़के पर और चार मेरे आदमियों पर दफा 436, 452, 379, 506, 107, 147 जितनी भी दफा लगा सकती थी हमें जेल भेजने के लिए केस तैयार कर लिया, हमें जेल भेज दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहां का न्याया है कि चीफ मिनिस्टर के नारे को ऊंचा करने के लिए उस आदमी की मदद की जाए और उसके एवज में हमारे खिलाफ झूठे मुकद्दमें बनाये जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात हाउस के अंदर कह सकता हूँ और आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, जो कुछ भी मैंने लिख कर दिया है उसके बारे में आप अपने द्वारा या किसी आदरणीय एम०एल०ए० द्वारा इसकी इन्क्वायरी कराये। अगर मैंने झूठा इल्जाम लगाया हो, अगर मैं गलत हूँ तो जो मुकद्दमें बने हैं उनकी सजा तो कोर्ट देगी ही लेकिन आप इस

जगह मुझे खड़े करके मालिके द्वारा 6 कोड़े मेरे भारीर पर लगवाये ताकि वे निगान यह बताये कि कोई बनिया एम०एल०ए० किसी आदमी के खिलाफ भविश्य में झूठे इल्जाम न लगा सके। अगर मेरी बात सच्ची है तो उस आदमी को कोई सजा आप दे सकें या न दे सकें उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपनी सफाई पैदा कर सकता हूँ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जिसकी कि यहां पर आजकल चर्चा चल रही है। आजकल प्राइवेट स्कूल और कालेज टीचरों और प्रोफैसर बहुत परेगान हैं, उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, वे हड़ताल पर बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार ने इस बीमारी की सही तह पर पहुंचने की कोशिश नहीं की है कि यह बीमारी क्यों है? आज हरियाणा में जितनी प्राइवेट संस्थाए हैं उनमें लगभग 6 लाख लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार का फर्ज सब लोगों को पढ़ाना है, अगर ये सारी प्राइवेट संस्थाओं को बन्द कर दें तो सरकार के पास एकदम से इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कोई साधन नहीं है। मैं एक मिनट में बात साफ कर देता हूँ कि असल बीमारी क्या है? डिप्टी स्पीकर साहब, स्कूल और कालेज दो तरीके से चल सकते हैं एक तरफ से सरकार की यह पालिसी है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या कालेज जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उससे ज्यादा फीस किसी लड़के से नहीं ले सकता दूसरी तरफ जब से कोठारी कमीगान की

रिक्मैडे ांज लागू हुई है तब से सरकार को यह पालिसी है कि कोई भी स्कूल या कालेज जो सरकार के ग्रेड है उनसे कम तनख्वाह नहीं दे सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, कोठारी कमी ान के बाद आप प्राइवेट स्कूलों की पोजी ान को देखे, स्कूल और कालेजों की फाईनै ाल पोजी ान की रीड करें कि उनमें कितना अन्तर है, उनकों कितना फाईनै ाल घाटा होने जा रह है। आज कितनी ऐसी संस्थाएं है जहां मैनेजिंग कमेटी तो उनकों छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन उनका घाआ पूरा नहीं होता। मैनेजिंग कमेटीज कालेजों और स्कूलों का इंतजम करने के लिए है लेकिन अगर उनकों यह कह दिया जाये कि जो दो लाख रूपये का घाटा है वह अपने घर से पूरा करें तो ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। मै यह बिल्कुल कंकरीट बात कहता हूं। हमारे जींद के अंदर गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर 1800 स्टूडेंट्स है और उनकों पढ़ाने के लिए 75 टीचर्स है लेकिन एक वहां पर एस०डी० हाई स्कूलों से बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन वहां परसात साल से टीचर्स को लगाने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है जबकि आज के हिसाब से वहां पर 75 टीचर्स होने चाहिये। पालिसी के हिसाब से सरकार को 75 टीचर्स की मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने 60 टीचर्स के लिए आज से पांच साल पहले एप्लाई किया था लेकिन आज तक कोई मंजूरी नहीं दी गई। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ध्यान दें कि इस वजह से कितना नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप हिसाब लगाये कि लड़कों की कितनी स्ट्रैंग्थ बढ़ी उतनी फीस बढ़ाकर तो सरकार ने

स्कूल की इन्कम में भामिल कर ली लेकिन 60 टीचर्स की जो सैव इन नही मिली और उनको तो तनख्वाह दे रहे है उस पर खर्च को वह स्कूल के खर्च में भामिल नही कर रहे है। इसलिए आप अंदाजा लगाये कि उस संस्था को कितना घाटा हो रहा है। (इस समय सभापतियों की सूची मेंसे एक सदस्य, चौधरी खुरीद अहमद, परासीन हुए) चेयरमैन साहब, अगर आप इसकी स्टडी करेगे तो आपको यह पता लग जायेगा कि प्राइवेट कालेज और स्कूल जो है आज उनकी बदतर हालत हो रही है, इसके लिए कसूरवार सरकार है, मैनेजिंग कमेटीज नही।.....

वित्त मंत्री (श्रीमूल चन्द जैन): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ इनफर्म इन हैं मेरे लायक दोस्त जो सवाल उठा रहे है, उसके बारे में हरियाणा सरकार ने इस बात इजाजत दे दी है कि जो प्राइवेट स्कूल में फालतु टीचर्स लगे है और जिनकी मंजूरी पिछले कई सालों से नही मिल रही थी, अब उनकी मंजूरी दे दी है।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, इसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं तो यह कह रहा था कि इसी समस्या की वजह से प्राइवेट स्कूलों और कालेजों की बड़ी बदतर पोजी इन हो रही थी, अगर सरकार इस पर विचार कर लेगी तो ठीक हो जायेगा।

श्री सभापति: उसकी मंजूरी हो चुकी है और विचार करने की स्टेज गुजर चुकी है।

श्री मांगे राम गुप्ता: बड़ी अच्छी बात है अगर मंजूरी हो चुकी है। चेयरमैन साहब, आज स्कूलों के बारों में, पढाई के बारों में बड़ी चर्चा चल रही है। आज कितने पढ़े लिखे बेकार हैं? चेयरमैन साहब, जब तक आप प्राइमरी क्लास के लड़कों की तरफ और टीचर्स की तरफ जोकि पढाई की नींव है, पूरा ध्यान नहीं देगे, तब तक पढाई का ढांचा सुधन नहीं सकेगा। आज का जो टीचर है वह इस बात क लिए मायूस हो चुका है। वह सिवाय अपनी ड्यूटी पूरी करने के और कुछ नहीं करता यानी उसका पढाने की तरफ ध्यान नहीं रहता इसलिए आप प्राइमरी स्कूलों की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें। मैं आपके जरिये सरकार को एक और बात कहना चाहता हूं कि यहां पर बड़े जोर से नारा लगाया जाता है कि किसान के लिए यह पहली सरकार बनी है, बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूं कि जब तक किसान को उसकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलेगी तब तक उसकी तरक्की नहीं हो सकती। अगर किसान की तरक्की नहीं होती है तो सारे देश के लोगों की भी तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि लगभग सभी लोग किसान की उपज पर निर्भर करते हैं। चेयरमैन साहब, इस बात पर बड़ी गहराई से विचार करना होगा। किसान की उपज के भावों के बारों में चौधरी हरस्वरूप बूरा जी ने यहां पर एक काल अटैन इन नोटिस पढ़कर सुनाया था। उसमें

था कि सरकार को यह चाहिए वह व्यापारियों को पाबंद करें कि इस कीमत से नीचे किसान की उपज कोई न खरीदे। चेयरमैन साहब, इसके ऊपर सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, कपास का भाव 330 रूपये निकला और जब वह कपास बिकने के लिए आई तो वह व्यापारी ने ली और व्यापारी ने उसे 220 रूपये के भाव बेचा यानी उसकों सौ रूपये क्विटल के हिसार से नुकसान हुआ। बाजरे का 90 रूपये का भाव निकला और बाद में वह 60 रूपये का बिका, वह भी नुकसान व्यापारी को हुआ। इसी तरह से गुड़ का भाव भी 90 रूपये निकला था लेकिन आज उसी गुड़ कोई 60 रूपये के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इसमें भी 30 रूपये क्विटल के हिसाब से व्यापारी को ही घाटा पड़ा। इसलिए आपको इस तरफ विचार करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है? (विधन) जहां तक स्पोर्ट प्राईस की बात है सरकार ने 85 रूपये का भाव बाजरे का बनाया हुआ है लेकिन हरियाणा की किसी भी मण्डी में सरकार ने एक क्विटल भी बाजरा नहीं खरीदा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार किसान का बाजरा स्पोर्ट प्राईस फिक्स करने का क्या फायदा। चेयरमैन साहब, इसी तरह से जीरी की बात, इसी तरह से गेहूं की बात हैं आपने गेहूं का भाव 112.50 रूपये बनाया 85—85 रूपये जीरी का भाव बनाया। चेयरमैन साहब, यह बात मैं कई दफा सुना चुका हूं कि किसान को कम कीमत देने के लिए जिम्मेदार है। ये कहते हैं कि व्यापारी 60 रूपये के हिसाब से जीरी लेकर अगले दिन उसे 85

रूपये के हिसाब से सरकार को बेच देता है, गेहूं को 90 रूपये के हिसाब से लेकर अगले दिन 112.50 रूपये में सरकार को देता है।

चेयरमैन साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और अपने तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि कोई ही ऐसा नीच व्यापारी होगा जो अपनी दुकान पर आए हुए किसान के माल के नीचे भाव पर खरीदना चाहता हो।

श्री सभापति: अब आप वाइंड-अप कीजिये।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, यह बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी ठीक नियत वाला व्यापारी 80 रूपये क्विटल की जीरी 60 रूपये क्विअल में नहीं खरीद सकता और 112 रूपये भाव की गेहू 90 रूपये के भाव में नहीं खरीद सकता अगर गवर्नमेंट और उसके मुलाजिमों की नियत ठीक हो। अकेले व्यापारी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आपके एक्ट के तहत हर मंडी में मार्किट बनी हुई है और सब जगह देरी सिस्टम है। जमींदरा की जो ढेरी आती है वह इन्सपैक्टर के रजिस्टर में लिखी जाती है। चेयरमैन साहब, आप और मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से नोट कर लें। अगर आपकी गवर्नमेंट और सारे सरकारी अफसर इस बात की तरफ तवज्जह दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यापारी हेरा फेरी नहीं सकेगा। जब तक व्यापारी के साथ सरकार कर्मचारी भागमिल नहीं होते तब तक वह अकेला हेरा फेरी कर ही नहीं सकता। चेयरमैन साहब, एक सौ साठे बारह रूपये गेहूं का

भाव निर्धारित किया गया था और 85 रुपये जीरी का भाव निर्धारित किया गया था लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर यह बात कहता हूँ कि किसान को 80-81 रुपये से ज्यादा जीरी का भाव नहीं दिया गया। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय मैं दुखी होकर मंडी में बोली के ऊपर चलता था और आपके अफसरों के साथ चलता था तो किसानों को दो रुपये की एवरेज से ज्यादा भाव मिलता था। इसका आप अंदाजा लगा लें कि अगर एक मंडी में 10 हजार क्विंटल जीरी आई हो तो उस दिन किसानों को 20 हजार रुपये का घाटा होता था। चेयरमैन साहब, आपको पता है कि जब जीरी का भाव 85 रुपये फिक्स है तो वही जीरी 80 रुपये क्यों ली जाती है। आप हैरान होंगे 80 रुपये के हिसार से जीरी ल लेकर करके उसी जीरी को अपने दिन पैसे लेकर 85 रुपये के हिसाब से खरीदी जाती है तो किसानों से 85 रुपये के हिसाब से वह क्यों नहीं खरीदी जा सकती? इसलिए आप खुद इसका अंदाजा लगायें या आप खुद इसकी रिपोर्ट तैयार कर लें कि जो जीरी 60 और 65 रुपये के हिसाब से बिकी या जो गेहूँ 90 और 95 के हिसाब से बिकी वह कहाँ गई? जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अपने दिन वह सारी की सारी उपज पैसे की सेटलमेंट की भरी गई। वह उपज कहीं आसमान में नहीं उड़ गई बल्कि वही पर उसका घोटाला होता रहता है। चेयरमैन साहब, आप अंदाजा लगायें कि अगर आपके अफसर ठीक हों तो यह जो भाव का जिक्र करके व्यापारियों और किसानों में फर्क करना चाहते हैं यह बात साफ तौर पर सामने आ

जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपके अफसर ठीक हों और एक भी व्यापारी इस किस्म की बदमाशी कर जाये तो मैं जो सजा चाहों भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसलिये पहले अपना ढांचा सुधारों।

श्री सभापति: कृपा अब आप वाइंड-अप कीजिए।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, आप बार बार वाइंड अप करने के लिये कह रहे हैं इसलिये मैं एक दो बातें और किसानों के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। चेयरमैन साहब, चौधरी हर स्वरूप बुरा ने भी किसानों की उपज के भाव के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन पे किया था लेकिन चेयरमैन साहब मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसान की भलाई के लिये केवल मोशन पे करना करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके लिये सरकार की कोई ठोस कदम उठाने पड़ेगे।

श्री सभापति: गुप्ता जी अब आप बैठिये।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार एम०एल०एज० को कारपोरेट्स और बोर्डज के चेयरमैन बनाने की बजाये इनकी कमेटी बनाये जोकि इस बात की निगरानी रखे कि किसानों की दिक्कत भी दूर होगी और क्रप्शन भी दूर होगी। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। कि आपने मुझ अपने विचार रखने का समय दिया।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद): चेयरमेन साहब, राजयपाल महोदय ने हरियाण विधान सभा क अधिवे ान के अवसर पर 28 फरवरी, 1979 को जो अभिभाषण दिया और जिसका आपने स्वागत किया और हमारी बहन सुशमा जी ने भी उसका समर्थनप किया मै भी उसकासमर्थन करने क लिये खड़ा हुआ है। आपको मै यह बताना चाहता हूं कि पिछले जो चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल थे वे किसी से मिलते नही थे और एम०एल०एज० उनसे बात करने से भी डरते थे। लेकिन आज हमारे चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री है, वे आम जनता को एम०एल०एज० होस्टल में सुबह के टाईम मिलते है ओर अपने घरपर भी मिलते है। इसके इलावा मै चौधरी देवी लाल जी को बंधाई देता हूं कि जब वे पहले पहल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होने एक नारा लगाया था कि "भ्रष्टाचार बन्द पानी का प्रबन्ध" भगवान ने उनकी बात सुनी ली। पानी का प्रबन्ध हो गया। हरियाणा के अन्दरा गांवों में बड़े जोरों का फ़्लड आया। मुझू अच्छी तरह से याद है कि हम गुडगांवा के अन्दर खुद गए थे। उस समय सारा गुडगांव जिला पानी के नीचे था। उस वक्त हमन `जहां जकर देखा कि किसानों की क्या हालत थी, मुझ अच्छी तरह से याद है कि वहां देहातों मे एक बांध का कार्य हो रहा था और वहां हमारे चौधरी देवी लाल जी, बहन डा० कमला वर्मा और बहुत से दूसरे एम०एल०एज० भी गये थे। वे खुद टोकरी उठाक कर उस बांध पर ले जा रहे थे। चेयरमैन साहब, एक कांग्रेस के तीनचार मैम्बर और वि ाल हरियाणा पार्टी के 5-6 मैम्बर जो

यहां पर इकट्ठे मिल गये थे। वे उस समय अपने अपने घरों में बड़ी ए गोड़ रात के सथ सो रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि आज यही लोग किसानों के लिये बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दो सालों के अन्दर जब हमने बांध बांध और जिला गुडगांव के अन्दर नहर खुदवाई उस वक्त ये लोग कहा थे? इसके अलावा मैं भाराब के बारे में भी कुछ कहूंगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि अगर भाराब बन्दी कर दी जाए तो हमारे हिन्दूस्तान का चरित्र ऊंचा और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। आज जिन अफसरान को भाराब चाहिए उन अफसरान के लिये आप भाराब को प्रबन्ध न करें, जिन पोलिटिकल आदमियों को भाराब चाहिए तो उनके लिये भी भाराब का प्रबन्ध न करें। यदि भाराब खत्म हो जाए तो काम ठीक हो सकता है। तो मैं आपके बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी ने सारे काम किसानों के हित के लिये किए हैं। ये सामने बैठने वाले लोग इस बात को क्यों भूल गये कि ये लोग किसानों को अमरजैसी में काटा करते थे, उनकी नसबन्दी करते थे।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप कीजिए।

श्री दीप चन्द भाटिया: चेयरमैन साहब, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जिला गुडगांव के अन्दर क्या क्या नहीं हुआ। जब नसबन्धी हो रही थी उस वक्त यही किसान पहाड़ों के अन्दर छिपे हुए थे जिन के लिये ये रो रहे हैं।

श्री सभापति: अब आप वाईड अप कीजिए।

श्री दीप चन्द भाटिया: आज ये किसानों के हित में बोल रहे हैं, इन्होंने किसानों के लिये क्या किया है, क्या इनको बोलते हुए भार्म नहीं आती? चेयरमैन साहब, फरीदाबाद में 15 हजार झुग्गी झोपड़िया है जिनमें गरीब किसान, गरीब मजदूर रहते हैं, उन पर इन्होंने बुलडोजन चलाकर बरबाद कर दिया, उनकी जबरदस्ती नसबन्दी कर दी और जो मेरी माताएं जो बच्चे जनने वाली थी बेरी तरह से मारी गईं। इनको यह कहते हुए भार्म नहीं आती कि आज की हकूमत खराब है? जनता पार्टी की हकूमत खराब नहीं, कांग्रेस पार्टी की हकूमत खराब थी जिन्होंने गरीब लोगों को उजाड़ कर रख दिया। क्या ये रिवास कांड को भूल गये? अगर रिवासकांड की कहानी कह दूं तो भार्म से हमार सर झुक जाता है यह किस आधार पर इस सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं? (व्यवधान) चेयरमैन साहब, आज ये सदन में बोलते हैं कि डा० मंगल सैन की कार का खर्चा बढ़ गया है, टेलीफोन पर खर्चा ज्यादा हो गया है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे पास दो टेलीफोन हैं, मेरा टेलीफोन का खर्चा 3 हजार रूपये का आया है, अगर डाक्टर मंगल सैन का इतना बिल आ गया तो कौन सी बाढ़ी बात है। मैं इनको बताना चाहता हू कि ये काम करते हैं और जो आदमी काम करेगा उसका इतना बिल तो आयेगा ही जो लोग रात को भाराब के नो में मस्त पड़े रहते हैं, उनका क्या

बिल आयेगा (व्यवधान) आज हमारे सामने जो ये बोल रहे हैं, मुझे 25-26 जून की रात अच्छी तरह से याद है जिस दिन मेरे घर पर 28-30 आदमी मुझे पकड़ने के लिए आए थे, ठाकर मोती सिंह उनके साथ थे। मैंने उन्हें कह कि पठान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है इन्होंने मेरे घर पर छापा मार और जब कचहरी में गये तो मेरे से लोगों ने सवाल पूछा कि क्या आपको मालूम नहीं कि स्टेट में एमरजेंसी लागू हो गई है। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था। मैंने ठाकुर मोती सिंह को कहा था कि मैं पोलिटिकल आदमी हूँ, देना का सेवल हूँ, अगर मुझे पकड़ना ही था तो चार पांच आदमी आ जाते, इतने आदमी आने की क्या जरूरत थी? न मैंने इन्दिरा का खू किया है, न बंसी लाल का किया है, न किसी और का किया है। ये लोग जिन्होंने गुनाह किए हैं, आज जनता पार्टी के राज में खुशियां मना रहे हैं क्योंकि हमने इन तमात लोगों को माफ कर दिया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड अप करे।

श्री दीप चन्द भाटिया: स्पीकर साहब, मुझे मुक्ति कल से टाईम मिला है, चौधरी खुरशद अहमद जी ने मुझे टाईम दे दिया। (व्यवधान) आपने तो देना नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप खत्म करे।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं आपके के द्वारा सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि फरीदाबा में गरीब मजदूर, गरीब किसान

झोपड़ियों में रहते हैं और ये लोग मवेशियों की तरह जिन्दगी बसर कर रहे हैं जो कि इन्सानों की जिन्दगी नहीं है। इनको कांग्रेस राज में बुल्डोजरों से काटा गया। फरीदाबाद कम्प्लैक्स वाले उनको अब पानी के नलके और बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है मैं चौधरी देवी लाल जी से और लोकल बाडीज मिनिस्टर चौधरी राम लाल वधवा से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दें। चौधरी राम लाल वधवा बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि खाली बैठने से गाड़ी नहीं चलेगी, आपको काम करना होगा। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि सरकार ने किसानों के लिये पानी का प्रबन्ध किया। 45 परसेंट रूपया जो भारत सरकार से मिला उसका 90 परसेंट रूपया किसानों को पानी देने के लिये खर्च कर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो जिम्मेदारी आपको मिली है। उसको सही ढंग से सरअंजाब देना आपकी ड्यूटी बनीती है। जब कोई भी किसी काम करने के लिए किसी हलके में जाएं तो वहां का एम०एल० वहां मौजूद होना चाहिए, यह नहीं कि हम हलके में न हों और मंत्री मोदय वहां चले जाएं। (व्यवधान) चौधरी राम लाल जी वहां जाएं तो हम वहां मौजूद होने चाहिए। चौधरी देवी लाल जी तो सब के लीडर हैं, उनके दिलों दिमाग में यह बात नहीं है कि पार्क में जाएं और खाली पत्थर पर अपना नाम लिख कर आ जाएं क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी कीमत पर ही ये लीडर बने हैं। (व्यवधान) मुझे चौधरी राम लाल जी के बारे में गिला नहीं है, मुझे गिला देवी लाल जी से है। (व्यवधान) मैं इनसे

अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं गरीब किसान हैं, उनकी हालत सुधारने के लिये लोकल बाड़ी मिनिस्टर और हाउसिंग बोर्ड के मिनिस्टर सभी मिलकर कोर्नर कोर्नर करें। हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बनते हैं वे सब दिल्ली वाले ले जाते हैं, इन गरीबों के हिस्से कुछ नहीं आता। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूँगा कि आप सैन्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इन झोपड़ी वालों को मकान बनाने के लिये जगह दे और कोर्नर कोर्नर करें कि ये लोग भी इन्सान की जिन्दगी बसर कर सकें। एक तरफ हम कोठियों में रहते हैं और दूसरी तरफ गरीबों के लिये झोपड़ियों के लिये भी जगह नहीं दी जाती। कम से कम एक कमरे की जगह तो दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपका समय हो गया है, आप खत्म करें।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं जनता सरकार का आभारी होऊँगा अगर वह इन गरीबों की सहायता करें। इन भावों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आपने मुझे समय दिया (विधन)

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी राजेन्द्र सिंह जी बोलेंगे।

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, अब बोलने का मेरा नम्बर है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट के लिये श्री राजेन्द्र सिंह जी बोलेंगे।

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, आपने मुझे टाईम देने का वायदा किया था। इसे बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने भी वायदा किया और बाद में चेयरमैन साहब ने वायदा किया (व्यवधान) अब क्या वजह है कि मुझे टाईम नहीं दिया जा रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह जी बोलेंगे, श्री हरफूल सिंह जी आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हरफूल सिंह: आपने मेरे से वायदा किया था, अब टाईम नहीं दे रहे, यह ठीक नहीं। (व्यवधान) बार बार मेरे से वायदे किये गये कि टाईम देगे, कम से कम चेयर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, मुझे टाईम मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद आपको टाईम दूंगा आप बैठ जाइए और हाउस का टाईम जाया न करें। (व्यवधान)

श्री हरफूल सिंह: पहले भी वायदा किया गया था और आपने भी वायदा किया था कि मुझे टाईम दिया जाएगा (विघ्न)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब असल बात यह है इन्होंने टाईम मांगा था और.....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैने चौधरी राजेन्द्र सिंह का काल-अपौन कर लिया है और मै अपना फैसला नही बदलता। इसके बाद अपोजी इन पार्टी के किसी मेम्बर को टाईम मिलेगा और उसे बाद इनको। (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मै आपसे एक अ योरेंस लेना चाहता हूं, सिर्फ एक मिनट लूंगा.....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्वायंअ आफ आर्डर पर बोले, अ येरेंस की बात न करें।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मै कह रहा हूं कि इस वक्त टाईम नही मिलता तो बजट पर बहस के मौके पर टाईम दे दें। आप हमं वि वास दिला दें कि उस वक्त टाईम या जाएगा।

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, टाईम बांटने का आपका तरीका क्या है?

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज टाईम बांटने का तरीका यह है कि अपोजी इन बैचिज और ट्रेजरी बैचिज की स्ट्रैंग्थ के अनुसार तथा अन्य हालत को देखते हुए मैं हर सदस्य को मैक्सिमम टाईम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो हर मैम्बर के बोलने के लिए पन्द्रह मिनट का टाईम फिक्स किया था और सारा हाउस उस बात पर एग्री कर गया था लेकिन उसके बावजूद बी बीस बी पच्चीस पच्चीस मिनट माननीय सदस्य ले गए। टाईम को मैं तो बढ़ा नहीं सकता हूँ। मैं बड़ी इम्पालियल्टी के साथ सै इन चला रहा हूँ। लेकिन इस वक्त अगर इस तरीके से टाईम जाया किया जाएगा तो लोगों को जरूरी टाईम कम मिलेगा।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, ऐसा करे लो, कि दोनों साथ-साथ बोल लें। (हंसी)

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की पिछली उपलब्धियों की चर्चा की है और सरकार का हमारे प्रदेश में जो तरक्की का आगामी प्रोग्राम है उसकी भी रूप रेखा सदन के सामने रखी है। राज्यपाल महोदय के इसी अभिभाषण पर सदन में चर्चा चल रही है और सदन के दोनों पक्षों के आदरणीय सदस्य अपने अपने विचार रख रहे हैं विपक्ष के मेरे कई साथियों ने न सिर्फ सरकार की कटु आलोचना की है बल्कि गवर्नर साहब ने अब अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया उस समय डिस्टरबैस क्रिएट करने

की कोर्िा की गई। मै सदन को अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहूंगा कि डैमोक्रेसी में जहां रूलिंग पार्टी के कुछ कर्तव्य है वहां अपोजी इन पार्टी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं इसलिये यहां अपोजी इन में बैठे सदस्यों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि अपोजी इन अपना रोल ठीक तरह से अदा न करें तो डैमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, अब मै राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पैरा दो और तीन की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इनमें राज्यपाल महोदय ने, सारे राज्य में बाढ़ से जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है उसकी चर्चा की है अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले गुड़गांव जिला का सोहना से लेकर के नूंह और फिरोजपुर झिरका तक का सारा इलाका हर बार बाढ़ में तबाह हो जाया करता था लेकिन पिछले दो साल से काफी ड्रेनेज और उजीना डाइव रिन आदि बनाकर सरकार ने काफी हद तक वहां के लोगों की प्रकृति के इस प्रकोप से बचाने की कोर्िा की है। मै इसके लिये सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य पाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और भी कई बातों की चर्चा की है। मै उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय थोड़ा दिया गया है लेकिन दो तीन बातें में सरकार के ध्यान में अव य लाना चाहूंगा। रिक्षा पद्धति के बारे में दोनों पक्षों के साथियों ने अपने अपने विचार रखे हैं यह बहुत ही अहम मसला बनत जा रहा है। इसलिये मै सरकार से

निवेदन करूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति के अन्दर भीघ्राति विघ्न परिवर्तन होना चाहिए ताकि आज जो हजारों ग्रेजुएट्स और लाखों मैट्रिकुलेट्स के नाम ऐम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में दर्ज होने के कारण समस्या पैदा हुई है वह कम हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हैं लेकिन आज वहां पर लेबर प्रॉब्लम की वजह से ला एंड आर्डर की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। मैं सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। गुड इयर फ़ैक्टरी में पन्द्रह सौ के करीब लेबर काम करती है लेकिन वह फ़ैक्टरी एक महीने से ज्यादा अर्से से बन्द पड़ी है। केन्द्र की सरकार को और हमारी हरियाणा सरकार को इसकी वजह से करोड़ों रूपये का नुकसान हो चुका है लेकिन आज तक सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर पाई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। इसके अलावा वहां और भी कई फ़ैक्टरीज है जैसे हैदराबाद ऐसबैस्टोज, अमरीकन युनिवर्सल ओसवाल, प्रताप स्टील आदि। इनमें भी रीजाना स्ट्राइक होती रहती है। इनके लीडर्ज जो है वे दूसरी स्टेट्स के है, उनका यही ऐम है कि किसी तरीके से ला एंड आर्डर को खराब सारे फ़ैक्टरी एरिया के अन्दर प्रोडक्शन को बन्द किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाईन्ड अप कीजिए।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री हरफूल सिंह (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो अपने मुझ बोलने के लिए टाईम दिया। मैं तो इसे आपका रहम समझता हूँ क्योंकि बोलने का मेरा हक बहुत पहले बनता था। खैर बात यह है कि गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बहुत से लोग बोले हैं और सबने अपनी अपनी राय हाउस के सामने रखी हैं अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाषण में बहुत सी बातें हैं जैसे कि बाढ़ की बात है, सिंचाई की बात है, सवा छः एकड़ जमीन पर मालिया माफ करने की बात है, ट्रैक्टरों पर टैक्स माफ करने की बात है और बेरोजगारी को दूर करने की बात है गांव में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर, चौधरी देवी लाल जी ने बहुत अच्छा एलान किया है कि गांव के पढ़े लिखे लड़के आपस में मिल जुल कर के अपना कोई धन्धा करें। यह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इस योजना के तहत गांव की अनेक जातियों के लड़के आपस में भाई भाई बन कर काम करेंगे। यह बहुत सराहनीय काम है।

स्पीकर साहब, बाढ़ की रोक थाम के लिये भी इस सरकार ने सिर्फ एक साल के अर्से में इतना काम किया है, जितना कांग्रेस की सरकार पिछले तीस सालों में नहीं कर सकी थी। यह भी बहुत तारीफ के योग्य काम है।

‘अनाज के बदले में काम’ वाली स्कीम भी चौधरी देवी लाल जी की बहुत बड़ी सोच है। कितनी अच्छी बात है कि लोग अपनी ही गलियां पक्की करें, सड़के बनाएं और दूसरे काम करें और उस मजदूरी के बदले अनाज ले ले। गरीब के लिये इतना बड़ा काम में समझता हूं कोई सरकार नहीं करेगी।

पानी का जहां तक ताल्लुक है, राव बीरेन्द्र सिंह जी ने तो यह कह कर अपना पीछा छुड़ा लिया कि बरसात आ गई लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बरसात भी अच्छी सोच का नतीजा है जिसकी नीयत अच्छी होगी उसी की मदद भगवान भी करते हैं।

मांगे राम गुप्ता जी ने भ्रष्टाचार की बात कही लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार तो अब नहीं है। भ्रष्टाचार तो उस समय था जब कांग्रेस सरकार में चन्दा उगाहने के लिये टारगेट मुकर्रर होते थे। उस समय अफसरों से कहा जाता था कि तुम एक लाख रूपया दोगे और तुम दो लाख रूपया दोगे। बी०डी०ओ०, एम०डी०ओ० और ऐग्जैक्टिव इंजीनियर आदि हमारे सामने कहते थे कि अगर हमने कोटा पूरा नहीं किया तो हमें बरखास्त कर दिया जाएगा लेकिन हमने उस सारे कोटा सिस्टम को हआ दिया। यह चौधरी देवी लाल जी की महेरबानी है कि आज किसी किसम का चन्दा नहीं उगाहा जाता। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उस समय तो अफसरों से यह कहा जाता था कि भाराब के मुकद्दमें जितने आपने पिछले साल बनाए थे उतने इस साल भी

बनाओं। मुकद्दमा वही बनाओं, जो सच्चा हो, झूठे मुकद्दमें न बनाओं। ऐसा करने से भ्रष्टाचार बन्द हो गया। यह सब कुछ चौधरी देवी लाल की सरकार में हुआ है।

स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक सुजै उन है, उसको मैं चीफ मिनिस्टर साहब और सिंचाई मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ। एम०आई०टी०सी० किसानों पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं चौधरी देवी लाल जी से और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कार्पोरे उन किसानों से खाल बनाने की साढ़े सताईस परसैन्ट डिपर्टमेंट का खर्चा चार्ज करती हैं इसको सिंचाई मंत्री महोदय ने कभी चैक नहीं किया है। किसानों पर साढ़े सोलह परसैन्ट ब्याज पड़ता है ब्याज पर ब्याज पड़ता है यानि कुल मिला कर 150 परसैन्ट खर्चा देना पड़ता है अगर उनके 100 रूपये लगे है तो हमसे 250 रूपये चार्ज करते हैं तीन एकड़ जमीन पर जो का त करता है उसको 180 रूपये देने पड़ते हैं इतना ब्याज तो कोई भी वसूल नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा 14 परसैन्ट ब्याज वसूल किया जात है परन्तु एम०आई०टी०सी० ने तो सब को पार कर दिया है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से और सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसको कम किया जाये। हम वर्ल्ड बैंक से एक परसैन्ट ब्याज पर पैसा लेते है तो किसान से साढ़े सोलह परसैन्ट क्यों चार्ज किया जाता है? यह बन्द होना चाहिए। इसको घटा कर एक परसैन्ट किया जाना चाहिए। किसानों से सौ रूपये

की जगह 250 रूपये वसूल नहीं किये जाने चाहिए। इन भावों के साथ मैं एक बार फिर आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर पूरी तरह से गौर किया जाए।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचानाकला): अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के एड्रेस पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि अब भायद कोई और सदस्य बोलने वाला नहीं है। मैं ही आखिरी बोलना वाला हूंगा। ट्रेजरी बैचिज के साथियों ने भी इन अभिभाषण पर अपने विचार रखे। इस अभिभाषण को सरकार तैयारकरती है, कैबेनिट या मुख्य मंत्री जी के निर्देशों पर कैबेनिट सैक्रेटरीज उसको भावत दते है। ट्रेजरी बैचिज की ओर से यह बात कही गई है कि यह अभिभाषण बड़े अच्छे आंकड़ों से और बड़े अच्छे ढंग से पे त किया गया। इसमें कहा गया है कि हरियाणा की जनता पार्टी गरीब आदमियों के लिये और किसानों के लिए बहुत काम करेगी। इसमें एक बात तो सही है कि एक घटक को छोड़कर मुख्य मंत्री और दूसरे मन्त्रियों की तो नीयत साफ है कि किसानों की जरूरत भला हो, गरीबों का भला हो लेकिन इस घटक की नीयत साफ नहीं है। (विधन)

मैं घटक के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो ये और भी ज्यादा नाराज हो जायेगे। इनके बहुत बड़े बड़े लीडर भी घटक की बातें कर रहे हैं। श्री मधुलिमये जैसे लीडर भी आज घटक की बातें कर रहे हैं मेरा कहने का मकसद यह है कि जनता पार्टी लोगों से वायदा करके आई थी कि हम कांग्रेस से अच्छा

भासने देगे और इसी कारण से लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिये थे लेकिन आज तक जनता पार्टी इस बात कोई सबूत जनता के सामने पे 1 नहीं कर पाई है। केन्द्रीय सरकार ने भी कोई ऐसा कार्य जनता के लिये नहीं किया जिससे जनता महसूस करें कि कांग्रेस से जनता पार्टी अच्छी है।

आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने खुले आम रेडियों पर और पालियामेंट के दोनों सदनों में एड्रेस करते हुए सरकार की कमिया बताई थी लेकिन गवर्नर साहब के एड्रेस में सरकार की तारीफ करने के सिवाये कुछ भी नहीं हं अगर जनता पार्टी की सरकार पुराने रीति-रिवाजों को तोड़ना चाहती ह तो गवर्नर साहब के एड्रेस में यह बात आनी चाहिए थी कि हरियाणा सरकार फ्लड को रोकने में ना-कामयाब रही है, हरियाणा सरकार एस०वाई०एल० का पानी लेने में ना-कामयाब रही है और गरीब देहातियों को रोजगार देने में ना-कामयाब रही है तब यह कहा जा सकता था कि यह सही ढंग से एड्रेस तैयार किया गया है स्पीकर साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी की नीयत साफ होने के बावजूद भी वे गरीब किसानों के लिये कुछ नहीं कर पा रहे है। भाहरों की अपेक्षा गांवों में कोई खास तरक्की नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप वाईन्ड-अप करें।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने यहां कहा कि तीस साल से वे स्वच्छ राजनीति में रहे हैं। उन्होंने यहां हाउस में बहुत लान्छन लगाये कि कांग्रेस ने दे आ को लुटा। मैं साफ बताऊंगा कि वे कैसे स्वच्छ राजनीति में रहे हैं। जब डाक्टर मंगल सैन जी होम मिनिस्टर थे तो हमारे यहां लड़ाई हो गई और एक आदमी मारा गया एस०पी० को टेलीफोन किया और जब एस०पी० नहीं मिला तो डी०एस०पी० को टेलीफोन किया कि कांग्रेस (आई) का एम०एल०ए० भी भामिल है, इसको भी रगड़ो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने उत्तर दिया था कि हम जनता की सेवा के लिए टूर करत हैं मैं इस बारे में यही कहूंगा कि वे 352 गांवों में तो जरूर गये होंगे लेकिन उनमें से एक का भी वे नाम बता दे तो मैं तो कहे वह सजा भुगतने के लिये तैयार हूँ। चौधरी देवी लाल की सरकार में पूंजीपतियां के एजेन्ट बने बैठे हैं।

सहकारिता एवं दुग्ध मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर है। क्या कोई मैम्बर किसी मिनिस्टर पर इस तरह से लान्छन लगा सकता है? यह उचित बात नहीं है यह हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज होना चाहिए।

Mr. Speaker: The hon. Member is insisting on his thing. I cannot get it expunged unless the Government benches would like to give me anything in writing.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल की सरकार में गांव के गरीब लोगों और किसानों की भलाई के कार्य करने में सब से बड़ी अड़चन एक ही है कि यह सरकार पूंजीपतियों और सरमायेदारों और साम्प्रदायिक तत्वों से धिरी बैठीर है और वे लोग किसानों और गरीब लोगों को भला नहीं होने देते।

हमारे दे 1 में एक लड़ाई यह चल रही थी कि भाहरों में बड़े अमीर आदमी रहते है ओर गांवों में बड़े गरीब आदमी रहते है इस अमीर और गरीब के फर्क को हम मिटाना चाहते थे लकिन इन चालाक लोगों ने उस लड़ाई को भाहर से हटा कर गांवों में चालू करवा दिया हैं इस बोरं में मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वे गावों की भलाई चाहते है कि हरियाणा में 20 नोटिफाइड एरिया कमेटीया है.....(व्यवधान)

श्री मूल चन्द मंगला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। हाउस में भाहरी और देहाती की बात करना भाोभा नहीं देता। ये तो भाहरी और देहाती को लड़ाने वाली बात कर रहे है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आप सदियों से उनका भाोशण करते चले आ रहे हो, इसलिये आज आप को तकलीफ हो रही है।

स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा में 20 नोटिफाइड एरिया कमेटीया है।

उन नोटिफाइड एरिया कमेटियों की आबादी से ज्यादा आबादी वाले 200 गांव हरियाणा में है लेकिन सरकार की तरफ से उनको तो सहूलियतें प्रदान की हुई है लेकिन गांवों को नहीं दी हुई है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि जिन गांवों की आबादी पांच हजार से ज्यादा है उनको भी वही सहूलियतें दी जाये जो उनको दी जाती है जैसे बिजली, पानी, सीवरेज, अस्पताल और स्कूल गांवों में भी माडल स्कूल के तरीके से स्कूल बनाये जाये।

श्री अध्यक्ष: बिजली और पानी की सहूलियत 5,000 से कम की आबादी वाले गांव को मिलनी चाहिए, क्या आपका यह मतलब है?

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: वह तो मिलनी ही चाहिए लेकिन जो टैक्स 13 म्युनिस्पल कमेटियों को ग्रान्ट वगैरा देने की वजह से लगाना पड़ता है, इनमें वह नहीं लेना चाहिए साढ़े 13 परसैन्ट टोटल बजट का इन 13 म्युनिस्पल कमेटियों को ग्रान्ट और लोन की भावत में जाता है। अगर यह पैसा इन्हें न देकर उन गांवों को जिनकी आबादी 5,000 से ऊपर है, उनको दिया जाये तो वहां पर वे तमाम सहूलियात पहुंच जाये जिनकी उन्हे तमन्ना हैं उससे एक सपना जो सरकार ने देखा था, मैं सरकार का सपना नहीं कहता, मैं उसे मुख्य मंत्री महोदय का सपना कहता हूं, या उनक कुछ साथियों का सपना कहता हूं, वह साकार हो सकता है। जब किसान को यह महसूस हो कि उसके लिये यह सरकार हमदर्दी के

साथ दिल के साथ कुछ काम रही है, तभी यह सपनापूरा हो सकता है लेकिन स्पीकर साहब अफसोस है.....(गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please wind up now.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: इन सार प्रयत्नों के होते हुए भी आज राज्य के अन्दर ला एण्ड आर्डर की इतनी खराब हालत हो चुकी है कि मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है। पहले तो यहां पर आदमी ही डाके डालते थे लेकिन अब औरतें भी डाके मारने लग गयी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर इतनी खराब ला एण्ड आर्डर की हालत हो गयी है कि कोई आदमी सेफ नहीं रहा सकता.....

Mr. Speaker: Please have your seat and I will now request the Hon. Chief Minister to reply to the Debate.

Ch. Birender Singh: Half-a minute more, sir.

Mr. Speaker: Please take your seat now. I have already given you five minutes more.

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): मोहतरिम स्पीकर साहब, जो गवर्नर साहिब के ऐड्रेस पर प्रस्ताव चौधरी खुर गिद अहमद ने मूव किया और जिसकी बहिन सुशमा ने ताईद की, उसकी बहस के दौरान मैंने अपने साथियों के विचार सुने और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि मिले-जुले ख्यालों के साथ ही एक ख्याल चाहे वह अपोजी गन का बोलने वाला था या ट्रेजरी बैन्चिज का, यह

आया कि इस सरकार ने काफी अच्छे काम किये है (थम्पिंग).....

...मै भाई बीरेन्द्र सिंह जी को मुबारिकवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को तो माना कि सरकार का जो सपना है, वह पूरा होना चाहिए। हमारा सपना यह है कि हरियाणा तरक्की करें और उस तरक्की में सभी लोग फले फूलें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ करने के बावजूद अपोजी इन बैन्चिज की तरफ से कुछ एतराजात आये है, उनका जवाब देना मै कुछ जरूरी समझता हूं। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि हैड वक्सर्ज का कन्ट्रोल जो हम अभी तक नहीं ले पाये है। यह हैड वक्सर्ज का कन्ट्रोल मेरे समय का नहीं, मेरे से पहली जो सरकार थी, यह उसका जमाने का है। यह उसका भी काम था। हम इसके लिये पूरी जद्दोजहद करते रहे हैं मै राव साहब को यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि यह अभी की बात नहीं, आज से बहुत दिन पहले हमारे प्राईम मिनिस्टर साहब ने एनर्जी मिनिस्टरको यह कह दिया था कि यह कन्ट्रोल जो है यह बी०एम० को दिलवाया जाये। इसके लिये हम गाफिल नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं एस०वाई०एल० की बाबत भी उन्होंने कहा। हम एस०वाई०एल० की बाबत भी उन्हें यह बताना चाहते है कि यह बड़ी मुद्दत से चीज चल रही है, हम उसके लियेभी पूरी कोशिश कर रहे है। उसकी बाबत यह कहा जा रहा है कि कही दोस्ती की वेदी पर हरियाणा का इन्ट्रैस्ट कुर्बान न कर दिया जाये, आप तसल्ली रखे कि कभी ऐसा मौका आया तो मै आपसे इस मामले में आगे मिलूंगा और मेरी सरकार भी आगे मिलेगी हम इसके लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं कई

दफा प्राईम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आ चुका है, कई दफा हमारी बकायादा मीटिंग भी हो चुकी है और अभी हम सैन्ट्रल सरकार पर अपनी तरह से पूरा दवाब डालने का यत्न कर रहे हैं कि एस०वाई०अल० की खुदाई का काम जल्दी से जल्दी हो। इस साल हमने इस एस०वाई०एल० के लिये 16 करोड़ रूपये रखे भी हैं।

अब उसे बाद ला एण्ड आर्डर की बाबत मैं कहना चाहता हूँ। ला एण्ड आर्डर का बड़ा सवाल उठाया गया। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा ला एण्ड आर्डर हो नहीं सकता। आपको हमारी इस सरकार की पुलिस की दाद देनी चाहिए कि उसने 17 लाख रूपये का स्मगलिंग का सोना पकड़ा और हमारी पुलिस ने उसके साथ ही पाकिस्तान से आये हुए कुछ लोगों को जिन्होंने भिवानी बैंक में डाका मारा था उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं 17 गैंग भी हमने पकड़े हैं। इसके साथ ही यहां पर यह कहा गया कि कत्ल के केसिज बढ़ गये हैं। पहले यह होता था कि कत्ल हो जाता था लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करते थे लेकिन अब सही मायनों में केसिज रजिस्टर होते हैं। पहली सरकार की तरफ हम गलत रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। होता खुदक गी का केस था, उसको कत्ल को केस बनाकर लोगों से रूपया ऐंठा जाता था और उसको भी रजिस्टर नहीं किया जाता था। पहले होता यह था कि कत्ल हो जाते थे लेकिन केसिज को रजिस्टर नहीं किया जाता था। इसके अलावा 293 जो कत्ल हुए

है उनमें से 213 केसिज में मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। इससे ज्यादा हमारी पुलिस और क्या कर सकती है? यही नहीं 107/151 दफा का पहले बहुत यूज होता था। पहले 48,000 लोगों को इस दफा के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हमने सिर्फ 24,000 लोगों को ही और वह भी अमनोअमान को कायम रखने के लिये पकड़ा था (व्यधान व भाोर).....यहां पर यह भी कहा गया कि जितने भी कमी न बिठाये गये हैं उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपकी मार्फत राव बीरेन्द्र सिंह और चौधरीर सुरजेवाल को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि रिवासा कांड जो है, इसे हमने ही उठाया था और कांग्रेस सरकार के टाईम पर यह कांड हुआ था। यह सारे हिन्दुस्तान में एक इ डु बन गया था। बार-बार हमने वहां पर पब्लिक मीटिंगे की लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस एजीटे न की कोई परवाह नहीं की। हमने गवर्नमैट बनते ही वहां के लिये भी एक कमी न बनाया कमी न की रिपोर्ट आने के बाद हमने वहां के एस०पी० और डी०सी० के खिलाफ दफा 302 के तहत केसिज दर्ज किये हैं और इस वजह से अपोजी न के बैचिज मूँ भी घबराहट आयी है पिपली और नगीना कांड की रिपोर्ट आने के बाद हमें कैबिनेट लेवल पर फैसला करना पड़ा। हमने दो डी०एस०पी०, दो एस०डी०ओ० एक बी०ओ०डी० और 5 कांस्टेबलज सस्पेंड किये हैं और उनके खिलाफ महकमाना कार्यवाही की गयी हैं इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि मिनिस्टरी बहुत बड़ी है। यह भी कहा गया कि एम०एल०एज० को कारपोरे नज का चेयरमैन बनाकर लालच दिया जा रहा है। यह

पोलिटीकल कुरुप ज्ञान की जा रही है। मैं राव साहब से पूछना चाहता था, वह तो है नहीं। सुरेवाला जी भी उस समय मंत्री थे, जब इनकी वजारत थी, तो उसको छोटा करने के लिये मैं लड़ाई लड़ा करता था, मुझे तभी पता लगा जब इन्होंने दिल्ली जाकर 8 मिनिस्टर और बना लिये और 27 मिनिस्टर इस तरह से उनके बन गये थे। मेरी मिनिस्ट्री में तो सिर्फ 15 ही हैं स्पीकरसाहब, जहां तक मैम्बर्ज को चेयरमैन बनाने का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि जितनी भी हमारी कारपोरे गन्ज थी, उनका पहले हाल यह था कि कहीं कोई इन्तजाम नहीं था। हाउस में पिछली दफा एक सवाल भी आया था। उसके बाद पब्लिक अन्डरटेकिंगज कमेटी भी बनाई गयी थी। उसका इलैव गन भी हुआ था। उसका चेयरमैन अब मेरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक लाला बलवन्त राय तायल को बनाया गया है इन पिछड़े हुए हालात को देखते हुए मैंने डैमोक्रेटिक ढंग से यह ठीक समझा कि एम०एसल०एज० के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाये। मैंने एम०एल०एज० के ऊपर यह जिम्मेवारी इसलिये डाली है क्योंकि वे पब्लिक के सामने जवाद देह तो है। अफसर अगर वहां पर हो तो वहा किसी के सामने जवाब देह नहीं है। उनकी तनुख्वाह और अलाउन्सिज के बारे में जो यहा कहा गया कि 10 हजार रूपयाएक चेयरमैन पर खर्च आता है, यह बिल्कुल गलत बात है उनके ऊपर सिर्फ 1000 से 2200 रूपये तक खर्च आता है मैं आपकी मार्फत यह बात आपके नोटिस में लाना चाहता था कि इस किस्म की गलत ब्यानी करना मुनासिब नहीं है बहिन सुशमा जी ने यह कहा कि एड्रेस तो ठीक है लेकिन उसमें स्पैसिफिक आंकड़े

नहीं हैं आंकड़े देने के बाद तो यह एक रिपोर्ट बन जाती है। जनरल वे में तो बहिन सुशमा जी ने भी इस गवर्नर साहब की तकरीर को पसन्द किया है। श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि पैदावार की कीमतें घटती जा रही हैं इसके बारे में तै सुरजेवाला जी को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जितने आंकड़े दिए हैं वे सही दिए हैं यह मैं मानता हूँ कि कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकी हैं और मैं यह भी मानता हूँ कि गन्दम के भाव के बारे में हमने लड़ाई लड़ी थी और हमने मोर्चा लगाया था और हमें पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त गन्दम का भाव 77 रूपया था। उसके बाद 105 रूपये हुआ और आज 112 रूपए है। भाव बढ़ता ही जा रहा है। हम गन्ने की बाबत मानते हैं, हम कपास की बाबत मानते हैं कि भाव कम है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि पैदावार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भाव के लिये भी कोशिश कर रहे हैं। आज से पौने दो महीने पहले जब चौधरी चरण सिंह ने फाइनेन्स पोर्टफोलियो सम्भाला था तो पांच सूबों के चीफ मिनिस्टर मिले थे और अभी पिछले दिनों 14 तारीख को 14 चीफ मिनिस्टर इकट्ठे होकर गए थे और उन्होंने कुछ सुझाव चौधरी साहब के सामने रखे थे और उनमें से कुछ सुझाव माने गए थे जिनसे इम्पोर्ट बन्द होगी और ऐक्सपोर्ट बढ़ेगी और इस तरह से कपास के भाव बढ़ेंगे और दूसरे अनाजों के भाव बढ़ेंगे। इसे साथ ही साथ पैदावार का जहां तक ताल्लुक है, मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। इसी हाउस में कुछ आंकड़े

पढ़कर सुनाए गए। कितनी गलत रिपोर्ट उन्होंने हमारे सामने पे की थी। स्पीकर साहब, 1965-66 में 19 लाख 85 हजार टन पैदावार थी जिसको उन्होंने 85 लाख बता दिया। उसके बाद 1966-67 में 25 लाख 92 हजार थी। 1967-68 में 39 लाख टन थी और 1968-69 में 27 लाख 64 हजार टन हुई और जब हमने जिम्मेवारी सम्भाली थी उस वक्त 50 लाख 38 हजार हजार टन थी और आज 53 लाख 61 हजार टन है और इससाल 58 लाख 78 हजार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि योजना के खत्म होने तक 65 लाख का निगाना पूरा कर पूरा कर लेगे। जहाँ भाव घट रहे हैं वहाँ पैदावार बढ़ा कर आमदनी बढ़ा रहे हैं और इस हिसाब के मुताबिक 6 लाख टन की पैदावार बढ़ी है। जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 60 करोड़ रुपया लोगों की जेबों में गया है स्पीकरसाहब जहाँ तक किसानों की सहूलियत देने का सवाल है हमने इनको हर किस्म की सहूलियत पहुँचाई हैं दो साल में तीन करोड़ रुपये की हमने सबसिडी दी है और इसके अलावा स्पीकरसाहब, मैंने यह नारा दिया था भ्रष्टाचार बन्द पानी का प्रबन्ध। स्पीकरसाहब, इनकी तरफ से बी सूत्री प्रोग्राम का नारा लगाया गया था और कहा गया था कि मेरे हाथ में राज दो मैं गरीबी हाटाउंगी और मेरे से बीस सूत्र होंगे। फिर इनके संजय पीछे क्यों रहने लगे। उन्होंने कहा कि चार मेरे सूत्र हैं इस तरह से चार बेटे के और बीस मां के सूत्र बताए गए और ये दोनों मिलकर 420 बन गए। हमने 420 की बात नहीं की, हमने तो दाहरफी बात की थी पानी का प्रबन्ध करेंगे और भ्रष्टाचार बन्द

करेंगे और स्पीकरसाहब, पानी का प्रबन्ध इस हिसाब से किया, पिछले दिनों जींद में एक जलसे में मैंने लोगों से पूछा कि चौधरियों पानी पिछले साल से अच्छा है या नहीं उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हुत अच्छा है ओर इस साल तो पिछले साल से अच्छा है या नहीं उन्होंने कहा कि चौधरी साहब बहुत अच्छा है और इस साल तो पिछले साल से भी अच्छा है। स्पीकर साहब अगले साल मैं तोबा करवा दूंगा और यह साबित भी कर दिया है आप टोहाना से लेकरबंडोपल, गोरखपुर, पाबड़ा इस नहर पर जाइए। आप मदीना, मैहम पर जाइए। आपको इसका सबूत मिल जाएगा। भिवानी ब्रान्च में सीपेज भुरू हैं हम इस सीपेज को खत्म करने के लिये कदम उठा रहे हैं और इसको दूर करने के लिए करोड़ों रूपया खर्च करने जा रहे हैं पहली सरकार ने जो कुछभी नहीं किया था। यह तो खजाना खाली करके गए थे। 48 करोड़ रूप्य का कर्जा छोड़कर गए थे हमने सीपेज को रोकने के लिए 191 करोड़ रूपया वर्ल्ड बैंक से लेकर काम भुरू किया है। पिछले दिनों वाटर कोर्सिज को लाइनिंग करने के लिए उद्घाटन किया गया है और हम इस काम पर करोड़ों रूपया खर्च कर रहे हैं ताकि किसान की पैदावार बढ़े। जहां पानी ज्यादा है वहां इन्तजाम कर रहे हैं कि सीपेज न हो। वहां सारी जगह लाइनिंग का इन्तजाम कर रहे हैं। नई-नई स्कीमें चालू की जा रही है और उस स्कीम के मुताबिक भिवानी के इलाके में भी भुरू कर रहे हैं। चौधरी सुरेन्द्र सिंह तो इस काम की तारीफ कर रहे हैं पता नहीं राव बीरेन्द्र सिंह पीछे क्यों हैं। राव बीरेन्द्र सिंह तो मुखालिफत कर रहे

हैं इनके इलाक़ों में स्पीकलिंग इरीगे टन स्कीम चल रही है और वहां पर लोग वाह-वाह कर रहे हैं। किसान की सहूलियत के लिए हमने पानी का प्रबन्ध किया है पानी का ठीक प्रबन्ध होने से पैदावार बढ़ी है। पैदावार के भाव बढ़ाने की हमारी कोशिश है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि किसान की ज्यो-ज्यो पैदावार बढ़े, उसको अच्छा मूल्य मिले और दूसरी सहूलियतें उनको दी जाए। स्पीकर साहब, हमने सिर्फ बात ही नहीं कि बल्कि हमने हर बात पर अमल किया है हमने सवा छः एकड़ पर लागन माफ कर दिया भाम डेर सिंह जी, मैंने इतना ही कहा था कि ट्रैक्टर किसान का गड्डा है। लोगों ने इसका मतलब यह ले लिया कि भायद हमारा टोकन अक्स माफ कर दिया गया है इस पर सवारियां जा सकती हैं, चालान नहीं हो सकता। चालान की बजाए पैसे लगी लगने लगी तो चर्चा होने लगी कि यह तो किसानका गड्डा है पैसे लगी लगने लगी। सुरजेवाला जी प्रजातन्त्र जो लोक राज है वह लोक लाज से चलता है। डंडे से नहीं चलना चाहिए। मैंने 150 रूपया टोकन टैक्स का माफ कर दिया। स्पीकर साहब, खाद और बीज का मैंने पहले ही कह दिया है। इसके साथ ही साथ अनाज को संभालने के लिए हमने यह इंतजाम किया है कि हर इलाक़ों के अन्दर गोदामों ताकि वह अपने अनाज को रख सकें और उसको बेचना न पड़े। जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अपने अनाज का 75 परसेंट गोदाम में रखकर उसके अगेन्सट 75 परसेंट पैसा लेकर अपनी जिन्दगी की जरूरत को पूरा कर सकें। इसके साथ ही साथ मुखतलिफ

डिवैलपमेंट के कामों की बाबत बताना चाहता हूँ। मेरे साथी भांकर लाल ने यह कहा कि मेरे हल्के में कोई भी सड़क नहीं मिली और मेरे हल्के में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। स्पीकर साहब, इनके हल्के में चार सड़क बन चुकी है और पांच सड़क जेरे तामीर है। यही कार कौड का मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया है। इन्होंने यह भी कहा कि सिरसा में हरिजन मोहल्लों और गरीब लोगों के मोहल्लों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई हैं मैं सदन को बतना चाहता हूँ कि सिरसा, रोहतक जहां कहीं भी यह रूपया दिया गया है दस लाख में दो लाख उन मोहल्ले के ऊपर खर्च करने की खास आदे । दिया है और इसके साथ ही साथ जो चालीस-चालीस साल के कब्जे थे उन्हें मालिकान हकूक देकर आया हूँ। स्पीकर साहब, इनके यहां इतने काम किए है। स्पीकरसाह, उस वक्त जनता मूव थी इसलिए चुकर आ गए वरना इन्का असैम्ब्ली में क्या काम था। आगे भी खड़े थे और जमानत जब्त हुई थी और आज ये सरकार की आलोचना करते है खैर ऐसा हीवक्त है। श्री बृजमोहन जी ने कहा कि जगाधारी रोड़ पर पुल का इन्तजाम नहीं है। स्पीकरसाहब, जगाधारी रोड़ पर पुल बन रहा है। इसके साथ-साथ अभी पिछले दिनों अम्बाला में सत्तर लाख के पुल का उद्घाटन करके आया हूँ। श्री िव प्र ाद वहां पर मौजूद थे। टांगरी के पुल को भी सत्तर लाख की लागत से बनेगा, उकस भी उद्घाटन करके आया हूँ और इसी तरह से अम्बाल के इलाके में करकांडा पर पचास लाख का पुल बनाया जाएगा। अब मैं चौधरी पोहलू की तरफ आत हूँ। इन्होंने कहा कि

मेरे यहां कोई सड़क नहीं बनी है और कोई स्कूल नहीं बना है। स्पीकर साहब, 39 गांवों में से 35 गांवों में सड़क जा चुकी है। चार बाकी रहते हैं। वहां पर भी काम चालू है। जहां तक स्कूल का ताल्लुक है, मेरी कोशिश है (व्यवधान)। राव राम नारायण ने शिकायत की कि मेरे इलाके को नजर अन्दाज किया जा रहा है, मेरे इलाके के साथ डिस्क्रीमिनेशन की जा रही है। स्पीकर साहब, इनके 14 गांवों में से दस गांवों में तो लिक रोड़ जा रही है और जो बाकी गांव इनके इल्के में रहते हैं वहां पर भी काम भुरु हैं उन्होंने खुशी जाहिर की कि चौपाल ते सब जगह बन रही है लेकिन सभी मिलजुल कर फायदा उठाएं। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत उनके इलाके की बाबत कहना चाहता हूं कि चौपाल हम सभी इलाकां मे बना रहे हैं और सब को तेजी से बना रहे लकिन जहां पर हल्के के मैम्बर दिलचस्पी न ले वहां बड़ी मुश्किल है। इसलिए मैंने इंट्रैस्ट क्रिएट कियाथा कि वहां एम०एल० के नाम से फाउन्डेशन स्टोन रखा जाए लेकिन हमारे राव साहब को एतराज यह है कि देवी लाल का नाम क्यों आए। स्पीकर साहब, मैं क्या करूं, मुझे लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया। वह तो यही कहेंगे कि फला चीफ मिनिस्टर के वक्त में उद्घाटन हुआ है। इसलिए इन्होंने अपने इलाके में चौपाल नहीं बनाई हालांकि इन हर डिप्टी कमिशनर को पांच दस लाख रूपया पे गी भेज चुके हैं।

स्पीकर साहब, भाई इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि फूड फारवर्ड एक बेगार है, इन्हे तो सुपीरिअरैलटी कम्पलैक्स है, इन्हे तो

यह बेगार ही नजर आता है। ये बठल थोड़ा उठा सकते हैं ये कस्सी उठा सकते हैं मैंने यह फैसला किया है और गांव गांव में जाकर यह कहता हूं कि आपकाम राके, आपको अनाज मिलेगा। और वह भी 100 रुपये क्विटल के हिसाब से जबकि बाजार में गन्दम को रेट 120 से 125 रुपये क्विटल है। अगर इस हालत में भी कोई काम न करें तो स्पीकरसाहब, फिर सरकार क्या करसकती है। इसी सिलसिले में हमारी सरकार अन-एम्पलायड एजुकेटिड के लिये रूरल इंडस्ट्रलाइजे इन का प्रोग्राम भुरु कर रही है। इसी 15 तारीख को हमारे सारे मंत्री और सभी बैंकों के मैनेजर, इंडस्ट्री आफिसर, लेबर-आफिसर वहां पर होंगे और उसी जगह पर हु एक साथ ही अपना काम भुरु करेगे और लोगों को कर्जा भी देगे। हरेक काम की सुविधा के लिए कोर्िा की जा रही है।

स्पीकर साहब, सन्त कंवज जी ने यह मांग की थी कि जो पब्लिक स्कूलज है उन्हें बंद कर दिया जाएं। यह सवाल हमारी नै इनल कौंसिल में भी आया था। उस वक्त बाबू जगजीवन राम जी ने भी यह कहा था कि स्कूल बन्द होने चाहिये क्योंकि गरीबों के लड़के वहा पर नहीं जा सकते। मैं भी इ तजवीज का हिमायती था लेकिन यह तजवीज कामयाब नहीं सकती, कुछ हालात ही ऐसे है लेकिन मैंने इन स्कूलों के मुकाबले में क्वालिटी स्कूलज् खोले है जिन में देहात के गरीबों के बच्चे और गरीब हरिजनों के बच्चे अपनी शिक्षा पा सकेंगे और उन में शिक्षा का स्टैन्डर्ड वही होगा जोकि पब्लिक स्कूलों में होता है जैसा कि राई का पब्लिक स्कूल

है। राई के स्कूल में दाखिले के वक्त यह किया गया है कि मैरिट के साथ साथ स्पोर्ट्सको भी ध्यान में रखा जाए ताकि गरीब और हरिजन बच्चों को दाखिले के वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और उन्हें भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी बात को देखते हुए, मैने मास्टर चन्दगी राम जोकि भारत का नही बल्कि दुनिया का एमा माना हुआ स्पोर्ट्समैन है, उसको वहां का एडी मानल डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दिया है और इस काम के लिये और ज्यादा फण्डज रख दिये है।

स्पीकर साहब, सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि भिवानी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है जो काम चल रहा है, उसको बन्द किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँकि हम किसी काम को बन्द नहीं कर रहे, हम ऐसे खर्चे को बन्द कर रहे है जो बिल्कुल फिजूल है जैसा कि सोनीपत में 13 सैट का और भिवानी में 18 सैट का रैस्ट हाउस हैं पिछले दिनों कुदरती मुझे वहां पर ठहरना पड़ गया, वैसे मैं अमूमन गांवों में ही ठहरता हूँ, बारि की वजह से मुझे वहां पर ठहरना पड़ गया। मैने वहां का सारा हिसाब किताब मंगवाया और उस हिसाब किताब को देखकर हैरान रह गया कि इनकी मेनटीनेन्स का जा खर्चा है वह 1 लाख 30 हजार है और इनसे जो आमदन होती है वह केवल 16 हजार है। ऐसे काम जो इनक बाप ने कर रखे थे, इनकों तो जरूर रोकूंगा। इसी तरह से जितने तो तरक्की के काम होंगे उनकों तो और बढ़ाया जाएगा। पानी के काम को बढ़ाया जाएगा। मैं यह मानता हूँ कि

भिवानी पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसक साथ साथ स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूँ कि हम लिफ्ट इरीगे इन के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं और मौजूदा साल में सिप्रकलिग इरीगे इन का काम जो है, वह पिछले साल क मुकाबले दोगुना हो चुका है।

स्पीकर साहब, अब मैं चौधरी भाम रेर सिंह जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बोलते हुए कहा कि पैदावार आगे से कम हुई है। पिछले कुछ सालों की पैदावार के आकड़े मैं यहां पर बता देता हूँ। सन् 71 में 47 लाख 71 हजार टन पैदावार थी और इस साल 61 लाख 78 हजार टन हो गई है। यह मैंने मोटा-मोटा जवाब दिया है इसी बारें में हमारे डाक्टर मंगल सैन जी ने काफी कुछ बताया है।

स्पीकर साहब, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारी अचीवमेंट्स क्या है। जिन दिनों हमारी जनता सरकार ने जिम्मेवारी सम्भाली, हमारा खजाना बिल्कुल खाली था। हमारे ऊपर 48 करोड़ रुपये का कर्जा था और फिर उसक साथ साथ सारे हरियाणा में बाढ़ भी आ गई थी। एक तिहाई हिस्सा हरियाणा का बाढ़ की लपेट में था। कहीं पर आने जाने का कोई साधन नहीं था। इस काम के लिये हमने पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा रुपया खर्च किया है। पहले केवल 2 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च नहीं हुआ था और इस साल हमने 19 करोड़ रुपया खर्च किया है और यह इसी ढंग से खर्च करते रहेगे। हमने बाढ़ों के बचाव क

लिये बड़ा कुछ किया और आगे करते आएंगे इस बारे में मैं अपने भाई खुरीद जी को बता देता हूँ कि आइन्दा के लिये यह जो फलड की जहनत है, यह रहमत साबित होगी। हमने कई जगहों पर बांध भी बना दिये हैं। इस बार मैं कई गांवों के अन्दर गया वहां देखा अब चचे आरम से धूम फिर रहे हैं अगर इस प्रकार का प्रबन्ध सरकार की तरफ से नहीं होता तो सारे के सारे गांव पानी में डूब जाते। स्पीकर साहब, हमने पानी को मीनों से निकाला। जैसा कि यहां पर कई साथियों ने कहा भी है। जहां पर पहले कहत पड़ता था अब वहां पर हरे भरे खेत लहरा रहे हैं और मैं हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि पहले से ज्यादा रिकार्ड तोड़ पैदावार होगी। मैंने जहनत को रहमत में बदलकर दिखा दिया है और ज्यादा को फिर्ता की जाएगी कि पैदावार और ज्यादा हो।

स्पीकर साहब, एक बात और इस हाउस में बताना चाहता हूँ जोकि खेतीबाड़ी से ताल्लुक रखती है। खेतीबाड़ी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। पिछली सरकार के वक्त में केवल 9 घण्टे बिजली मिलती थी और वह भी रात को, दिन में नहीं थी। चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला ने दिन में कहीं आसमान में बिजली चमकती देख ली होगी और अब हालत यह है कि 24 घण्टे बिजली मिलती है (तालियां) और इसकी बदौलत हम हर साल 18 हजार ट्यूबवैल्ज के नये कनेक्शन देते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमने पीने के पानी की भी मुश्किलों को दूर किया है। मेरे बहुत सारे भाईयों को पता होगा कि पहले

हरियाणा में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी, लोग जोहड़ों का पानी पीया करते थे। भाई सुरेन्द्र ने भी भायद जोहड़ का पानी पीया होगा, उससे कई किस्म की बीमारियां हो जाती थी, रारवा और दूसरी नाढ की बीमारियां, मैं भी इन्हीं बीमारियों का शिकार राह हूं लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी मुहैया किया जा रहा है। अब हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां पर चार पांच गांव हो वहां पर वाटर वर्कस का इन्तजाम किया जाए। 125 वाटर वर्कस पिछले साल बनाये गये हैं, इस साल और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरजेवाला जी, आपने पिंजौर गार्डन व बंगलौर का वृन्दावन गार्डन भी देखा होगा, वही नमूना हम अपने हरियाणा में अपना रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि हर पांच पांच गांव के बीच में छोटा सा वृन्दावन गार्डन होगा, फव्वारे चलते होंगे (तालियां) मेरे पास बड़े लायक इंजीनियर हैं, उनकी काबिलियत दूर दूर तक मालूम है। पीछे हमारी एक चीफ मिनिस्टर्ज की कांफ्रेंस हुई थी, उसमें भोख अबदुल्ला ने मुझे कहा कि आप हमें मिस्त्री लाल को दे दो, हम भी अपने वहां खूबसूरती लाना चाहते हैं तो मैं। सोचने लगा कि यह मिस्त्रीलाल कौन है, पता करने पर यह पता चला कि श्री एस.के. मिस्त्रा है। लोगों में यह गलतफहमी फैल रही होगी लेकिन मैं हाउस को बता दूं कि मैं सोहना रैस्ट हाउस में ठहरा हुआ था वहां का वातावरण देख कर मैंने सोचा कि बनाने वाले ने भी यह जगह खूब बनाई। भाई चांस उसी समय मिश्रा साहब आ गये। कहने लगे कि मैं एक्सटेंसन के लिए आया हूं। मैंने कहा

एसक्टैँ ान का क्या करोगे जाओ और अपनी जिम्मेदारी संभालो। तो मैं तो काम करने वाले आदमी की कदर करता हूँ। स्पीकर साहब, मैं वाटर सप्लाई की बात कर रहा था। पिछले साल के मुकाबिले में हम इस साल वाटर सप्लाई का काम दोगुना कर रहे हैं और मैं इसके लिए सरदार लछमन सिंह को मुबारिकबाद देता हूँ कि वे बहुत जोरों से इस काम में लगे हुए हैं। क्योंकि इनको इस काम में बहुत दिलचस्पी है इसलिए मैंने इनको ये दोनों महकमे दिये हैं। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है उसके बारे में मैं सुरजेवाला जी को यह कह सकता हूँ कि अगली इलैक् ान में अगर हमारा कोई उम्मीदवार जीप पर, घोड़े पर या ऊंट पर आए तो वोट न देना यानी अगर वह कार पर न पहुंचे तो वह वोट का हकदार नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब जगह सड़कें बना देंगे। जब जगह जगह खुाहाली हो जाती है तो लोगों का भाराब पीने को दिल करता है। हमने यह भी फैसला किया है कि लोगों की कमाई गलत कामों में न लगे इसलिये हमने प्रोहिब ान लागू करने का फैसला किया है। इस पालिसी के तहत हमने 20 फीसदी भाराब की मिकदार पिछले साल घटायी और 20 फीसदी इस साल घटायी। हमने एक और फैसला लिया है कि भाहरों में जो भाराब की दुकानें हैं इस साल से उनको भी कम किया जाएगा और उनको नीलामी के द्वारा दिया जाएगा। प्रोहिब ान के साथ साथ हम नये स्कूल और हस्पताल भी बना रहे हैं। लेकिन जब कहीं हस्पताल बनाने की बात आती है तो सबसे पहले यहां पर चुटाला का नाम आ जाता है। मैं सदन को बताना

चाहता हूँ कि चुटाला एक हिस्टारिकल गांव है और यहां पर उस अकेले गांव के तीन एम.एल.एज. हैं। हर एक एम.एल.ए. यह मांग करता है कि मेरे हल्के में ज्यादा स ज्यादा काम हो तो अगर चुटाला में जहां तक तीन एम.एल.एज. हैं एक हस्पताल बना दिया गया है तो कोई गलत काम नहीं हुआ है। जब एक गांव से तीन एम.एल.एज. यहां पर हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग हमारी कदर करते हैं और वहां पर हमारा असर है। हमने सिर्फ चुटाला में ही हस्पताल नहीं खोला है इसके अलावा कलानौर में , वालू में और नारनौंद में भी बनाया है। जहां पर जरूरत है वहां पर हर जगह हम हस्पताल खोलने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में हमने यह फैसला किया है और मैंने कल भी कहा था कि कहीं के लोग स्कूल खोलने के लिए अगर कन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उतना ही पैसा सरकार अपने पास से देगी। हर बड़े गांव में सरकार स्कूल बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे हमारे फाइनेन्सियल हमें इजाजत देते हैं उसके मुताबिक हम पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोग हमें तंग भी बहुत करते हैं। पांच पांच और दस दस सरपंच आ जाते हैं और कहते हैं वीरेन्द्र सिंह जी यह हमारा छोरा है इसको नौकरी पर लगा दो। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी मुझे कह देते हैं कि चौधरी साहब क्या करें इतने सारे सरपंच आ गये हैं, इस छोरे को लगा दो। मैंने कहा भीत में लगा दूँ। अगर हम इस काम में दखल भी दे तब भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि पांच पोस्टें खाली होती है और उनके लिए पांच हजार

कैंडीडेट्स आते हैं। पिछली बार पुलिस में भरती हुई तो हर जिले से पांच पांच हजार कैंडीडेट्स आये। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने रूरल इंडस्ट्रिआइजे इन की स्कीम भुरू की है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ओर बताता हूँ कि पिछले दिनों मुझे मेरा एक साथी मिला उसने मुझे कहा कि चौधरी साहब मेरा सेल्ज टैक्स का मामला है। मैंने कहा आप मुझे एक दख्तास्त दे दो, मैं पता करवा लूंगा। फिर वह कहने लगा कि मेरी सबसिडी रूकी हुई है तो मैंने कहा कितनी है ? तो कहने लगा थोड़ी सी है सिर्फ 1 लाख 20 हजार रुपये की। मैंने यहां आते ही सारी रिपोर्ट मंगवाई और पता लगा कि किसी को 38 लाख की सबसिडी दे रखी थी और किसी को 15 लाख की दे रखी थी उसकी बजाये अब यह जो रूरल इंडस्ट्रिआइजे इन की स्कीम भुरू हो रही है इसके तहत हम रूरल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए सबको 15 परसेंट पे ागी के तौर पर देंगे ताकि वे अपना काम भुरू कर सकें। सरकार को इस काम में डाक्टर साहब का बहुत सहयोग मिल रहा क्योंकि वे बहुत लगन से इस काम को कर रहे हैं। हमारी कोि । । यह है जितने यूनिट्स इस साल खोलने का हमारा विचार है भायद उससे ज्यादा ही खोल पाएं। पिछले दिनों राव बीरेन्द्र सिंह ने भिवानी के एक जलसे में कहा कि मैंने किसानों का पीछा छोड़ दिया है क्योंकि किसानों ने अपना लीडर और बना लिया है इसलिए मैं तो अब गरीब हरिजनों की सेवा करूंगा। उनकी सेवा का यह सबूत है कि हरिजनों के लिए जो चौपाले हमने बनाई उसकी वे मुखालफित करते हैं जिस इलाके में

कोई चौपाल बनती है तो उद्घाटन के समय पत्थर पर उस इलाके के एम.एल.ए. का नाम आता है ये इस बात की भी मुखलिफत करते हैं कि एम.एल.ए. का नाम क्यों आता है। खैर मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नारा है यह उस किस्म का नहीं है जिस किस्म का इन्दिरा का नारा था। हम महज थोथा नारा नहीं लगा रहे हैं बल्कि हम तो हरिजनों का पूरा ख्याल रखते हैं। हमने उनके लिए बहुत कुछ करने का फैसला किया है। पिछड़ी जातियां जो हैं उनके लिए पहले 2 प्रति आत रिजर्वे आन होती थी लेकिन हमारी सरकार ने 5 प्रति आत कर दी है। यही नहीं कि हमने उनको नौकरी में लिया है बल्कि हमने सिलैक आन बोर्ड का चेयरमैन भी बैकवर्ड क्लास का बनाया है और इसके अलावा चार एम.एल.एज. भी बनाए हैं। पिछले दिनों राव साहब ने नारनौल के इलाके में एक जलसे में कहा कि देवी लाल ने कहा है कि मैं लोगों की गर्दन सीधी करता हूँ। मैंने यह नहीं कहा था मैंने तो यह कहा था कि मैं लोगों की मदद से पिछले इलैक आन में बड़ी लहर चली और मनोहर लाल सैनी जैसा एक साधारण व्यक्ति वहां से जीता और जिन लोगों की गर्दन सीधी नहीं होती थी उनकी गर्दन लोगों ने सीधी कर दी। तो मैंने तो यह कहा गर्दन लोगों ने सीधी कर दी। स्पीकर साहब, हम बैकवर्ड क्लासिज को हर किस्म की मदद देने की कोशिश कर रहे हैं।

एक आवाज: बैकवर्ड क्लासिज की आबादी के लिहाज से रिजर्वे आन करो।

चौधरी देवी लाल: आबादी के लिहाज से रिजर्वे इन के लिए हमें थोड़ा सा टाईम दो। यह जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। चालीस साल तक जेलों में रह रह कर आज यहां पहुंचा हूं। पिछली सरकार के टाईम में चौधरी बंसी लाल ने मुझे कहा कि चौधरी साहब आपकी सीट तो फलां है तो मैंने कहा कि मेरी सीट तो गलती से अपोजी इन में आ गई, मेरी सीट तो यहां होनी चाहिए थीं। स्पीकर साहब जहां तक तालीम का तालुक है जिन कालेजों की हालत खराब है उनकी हालत सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो जिन स्कूल कालेजों की माली हालत खराब है दूसरे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इन काफी खराब है जिनके प्रोफेसर हड़ताल पर रहते हैं, बच्चे हड़ताल पर रहते हैं ऐसे स्कूल व कालेज अब 75 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गये हैं जबकि कांग्रेस के जमाने में केवल 30 फीसदी कालेजों की हालत ठीक थी और ये अपने आप को बड़े तीस मारखां समझते थे। कांग्रेस सरकार के वक्त में जहां हड़ताल चलती थी वहां कानून बना दिया जाता था लेकिन आम सुधार के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती थी। अब इन सारी बातों के लिए इन्क्वायरी करने की कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कालेज चल सकता है कि नहीं और उनको सुधारने की भी कोशिश की जायेगी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की बाबत भी कहा गया कि अच्छा इंतजाम नहीं है और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं खुद, जहां से रिटायरत आई वहां गया मैंने चैंकिंग करने के लिए पुलिस को भी ड्यूटी लगाई क्योंकि ट्रांसपोर्ट के इन्स्पैक्टर अच्छी

तरह से चैकिंग नहीं कर सकते, उन पर अपने यूनियन का दबाव होता है। पुलिस की डियूटीर लगाने का असार यह हुआ है कि कई जगह पोहलू साहब के कहने से या उनकी राय सुनने से मैंने मैनेजमेंट को जहां दोशी पाया उसे सजा दी जैसे पीछे जनरल मैनेजर को सस्पेंड किया। कई जगह सही मैनेजमेंट देखने के लिए छापे भी मारे जहां कई जगहों पर चोरी का माल बरामद हुआ है। हम कोि । । कर रहे हैं कि प्रांत में ट्रांसपोर्ट के बारे में लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाये। मैं एक बार टूर पर गया था और रास्ते में मुलाना थाना पड़ता था उसके 30 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर उधर से बसें भर कर आत हैं पर उस जगह पर सवारियां लेने के लिए बसें खड़ी नहीं होती हैं। सवारियों की दिक्कत दूर करने के लिए हमने वहां लोकल बस चलाने का फैसला किया है। ऐसे रूटों पर लोकल बसिज चलाने का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि इन बसों द्वारा भी सरकार का प्रचार होता है कि सरकार कैसी है। सरकार की अच्छाई का प्रचार ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत निर्भर करता है। इसका भासन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग ट्रांसपोर्ट सेवा को जिसके बारे में हमारे अपोजी ।न के साथियों ने हैल्दी क्रिटीसिज्म करके हमारा ध्यान दिलाया है, बहुत अच्छा बनाने की कोि । । करेंगे। स्पीकर साहब, राव साहब ने कहा था कि हमारे इलाके को नजर अंदाज किया जा रहा है। वे अपने इलाके के एक भी अहीरों के किसी भी बड़े गांव का नाम बता दें वहां हम लड़कियों का सरकारी स्कूल बना देंगे और जहां अस्पताल नहीं है वहां 25-25 बैड्स के

अस्पताल खोल देंगे ताकि वहां के लोग अपना ईलाज करवा सकें। आज जो अपोजी इन के सदस्यों ने सरकार की सराहना की है, मैं उनका म आकूर हूँ। इन लफ्जों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जो चौधरी खुर गीद अहमद ने इस हाउस में रखा और जिसकी सुशामा बहन ने ताईद की।

Mr. Speaker: Now I will put the amendment by Sarvshri Birender Singh Rao, Shamsheer Singh urjewala, Dalip Singh Rao, Surrender Singh, Jagjit Singh Pohloo, Narain Singh, Inderjit Singh and Mange Ram Gupta to the vote of the House.

Dr. Mangal Sein: They are withdrawing it.

Sh. Shamsheer Singh: We are not withdrawing it.

Mr. Speaker: Then I will put it to the vote of the House.

Question is:-

That in the motion, the following be added at the end, namely:-

- 1) but regret that it has failed to mention the deteriorating Law & Orde situation in the State resulting in sharp increase in incidents of murders, dacoities, thefts, highway robberies, rape etc;
- 2) but regret that it does not contain any proposal for solving the ever increasing unemployment among the

- educated unemployed in the State and failed to provide the unemployment allowance;
- 3) but regret that there is no mention of the serious unrest amongst the students in the universities;
 - 4) but regret that there is no mention of relief to the Traders in the matter of sales tax, Market Fee and to remove the rigours of Food Adulteration Act;
 - 5) but regret that there is no mention regarding the amelioration of the lot of Harijans, including the Safai Karamcharis;
 - 6) but regret that there is no mention of securing the transfer to control of canal Head works situated in Punjab to the Bhakra Management Board, as decided by the Central Government;
 - 7) but regret that there is no mention of transfer of Fazilka – Abohar and other Hindi speaking areas, left out in Punjab, to Haryana;
 - 8) but regret that there is no mention of atrocities being committed against minority community residing in Gurgaon District;
 - 9) but regret that there is no mention of concrete proposals/steps for securing remunerative prices of agricultural produce;
 - 10) but regret that there is no mention of the prevailing unrest and large scale retrenchment, lay-offs, lock-outs

and repression let loose on the industrial workers in the State; and

- 11) but regret that there is no mention of the large-scale persecutions, harassment and victimisation of the political opponents by the Janta Party Government in the State;

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now I will put the main motion to the vote of the House.

Question is:-

“That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

“That the members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 28th February, 1979.”

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 7th March, 1979.

18.24 Hours

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday the 7th March, 1979)